● वर्ष-2
● अंक-230
रायपुर, गुरुवार
18 मई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

भारत में धर्म परिवर्तन एक लाख करोड़ का कारोबार

खाड़ी और पश्चिमी देशों से भारत में सालाना 50-50 हजार करोड़ रुपए एफसीआरए के जरिये आ रहा

नई दिल्ली। देशभर में बढ़ती धर्मांतरण की घटनाओं और इस समस्या से निजात दिलाने के उपायों की लेकिन जरा उससे पहले आपको कुछ एकदम ताजा समाचार बताते हैं ताकि आपको पता चल सके कि पढ़ लिख कर तेजी से आगे बढ़ते हुए न्यू इंडिया में भी कैसे धर्म परिवर्तन के नाम पर गहरी साजिश चल रही है और लोग इसके आसानी से शिकार हो रहे हैं।

सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश से हाल ही में आई उस खबर की जिसके मुताबिक कट्टरपंथी संगठन हिज्ब उत तहरीर (एचयूटी) से जुड़ाव रखने के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक प्रोफेसर और एक जिम ट्रेनर सहित ऐसे लोग शामिल हैं जो कि प्रथम दृष्टया 'लव जिहाद' और धर्म परिवर्तन के मामलों में शामिल थे। इस मामले में रोजाना जो नये नये खुलासे हो रहे हैं उससे सियासी पारा भी चढ़ गया है। मध्य प्रदेश में सौरभ राजवैद्य के सलीम बनने के पीछे जाकिर नाईक की भूमिका भी बतायी जा रही है। जब भोपाल का सौरभ कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर सलीम बन गया और एटीएस की एक कार्रवाई के दौरान हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया जब जाकर इस सारे षड्यंत्र का खुलासा हुआ। अब यह संयोग है या प्रयोग यह तो पता नहीं लेकिन जरा आप देखिये कि सौरभ से सलीम बना युवक हैदराबाद में एक आतंकी गुट का चीफ बताया जा रहा है और दिखावे के लिए वह एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। देखा जाये तो ब्रेन वाश करके धर्म परिवर्तन करने की साजिश के बारे में समाचार सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं देश के विभिन्न भागों से रोजाना सामने आ रहे हैं। इसके अलावा,

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से खबर आई कि संदीपन घाट क्षेत्र में बीमारी ठीक करने तथा अन्य प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि संदीपन घाट थाना क्षेत्र के सैंता गांव में बीमारी ठीक करने और अन्य कई प्रलोभन देकर गरीब ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास की सूचना पर पुलिस ने गांव में छापा मारा। उन्होंने कहा कि लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देने के आरोप में महाराज सरोज, उमाकांत मौर्य, महेंद्र कुमार तथा वेद प्रकाश को गिरफ्तार किया गया।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा क्षेत्र में एक महिला को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में एक पादरी और उसकी पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मधु विहार कॉलोनी में रहने वालीं भाजपा कार्यकर्ता सुनीता अरोड़ा की शिकायत पर पुलिस ने पादरी इब्राहिम थॉमस, उनकी पत्नी रीवा और ब्यूटी पार्लर संचालक बबिता को गिरफ्तार किया। सुनीता ने शुक्रवार की रात खोड़ा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी पड़ोसी बबिता ने उन्हें केरल के मूल निवासी इब्राहिम थॉमस से मिलवाया था जो वर्तमान में कलवरी चर्च में पादरी है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि थॉमस अपनी पत्नी रीवा की मदद से धर्मांतरण के लिए हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों के लिए धार्मिक सत्रों का आयोजन करते हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि थॉमस ने बबिता की मदद से भाजपा की कार्यकर्ता सुनीता अरोड़ा को पार्लर में बुलाया और उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया। यह खबरें मात्र कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार की साजिशें देशभर में चल रही हैं क्योंकि धर्मांतरण अब एक व्यवसाय का रूप ले चुका है।

धर्म परिवर्तन आखिर है क्या?

आज की तारीख में धर्म-परिवर्तन के नाम पर ताकत का खेल है। इसका एक मात्र उद्देश्य अपने-अपने समुदाय का संख्या-बल बढ़ाना है। वैसे भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में संख्या-बल के आधार पर ही सत्ता पर कब्जा होता है। सिर्फ सत्ता पर औपचारिक कब्जा ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अपना वर्चस्व कायम करने में मजहबी-संख्या की जबर्दस्त भूमिका होती है। यहां सवाल यह भी उठता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपना धर्म-परिवर्तन करता है तो क्या वह वेद, त्रिपिटक, बाइबिल, जिंदावस्ता, कुरान या गुरु ग्रंथसाहिब पढ़कर और समझकर करता है? यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ या विचारधारा को सोच-समझकर उसमें दीक्षित होना चाहता है तो उसे परमात्मा भी नहीं रोक सकता लेकिन जो व्यक्ति लालच, भय, प्रतिरोध, अज्ञान और ठगी के कारण धर्म-परिवर्तन करता है, उसे वैसा करने से जरूर रोका जाना चाहिए।

इतना बड़ा व्यवसाय कैसे?

हमने जब इस बारे में भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अश्विनी उपाध्याय से बात की तो उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि धर्मांतरण एक लाख करोड़ रुपए का सालाना व्यवसाय है इसलिए यह आसानी से रुकने वाला नहीं है। खाड़ी देशों से भारत में सालाना 50 हजार करोड़ रुपए हवाला के जरिये और पश्चिमी देशों से भी सालाना पचास हजार करोड़ रुपए एफसीआरए के जरिये आ रहा है जिसे रोके जाने की जरूरत है।जब तक जबरन धर्म परिवर्तन कराने के जुर्म में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान नहीं किया जायेगा तब तक यह समस्या बरकरार रहेगी। जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने पर कुछ सालों की सजा नहीं बल्कि कठोर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि दुनिया में कई देशों में इस तरह के प्रावधान हैं इसलिए हमें भी धर्मांतरण कराने वालों को कतई बख्शना नहीं चाहिए। बहरहाल, देखा जाये तो हम धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश करने वाली फिल्म द केरला स्टोरी का विरोध तो कर रहे हैं मगर पीएफआई, हिज्ब उत तहरीर और उन मिशनरी संगठनों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे जो कभी बीमारी ठीक करने के नाम पर तो कभी आर्थिक प्रलोभन के नाम पर तो कभी हिंदुओं के खिलाफ जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं।

इन दिनों

✍ शशांक शर्मा

लोक सेवा आयोग पर उठते सवाल

राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसका कार्य द्वितीय एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती करना होता है। इस संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों को विशेष संरक्षण प्राप्त होता है, उन्हें पद से सरकार आसानी से हटा नहीं सकती। ऐसी शक्ति इसलिए दी गई है ताकि पदों पर नियुक्ति करते समय सरकार का उनपर दबाव न हो और निष्पक्षता से अपना कार्य कर सकें। अभी हाल में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित हुआ है। इसके सर्वोच्च पदों की सूची में अनेक नाम बड़े अधिकारियों और नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों के हैं। इस कारण पीएससी की कार्यप्रणाली पर संदेह खड़े हो रहे हैं। वैसे तो किसी अधिकारी या नेता के बच्चे या रिश्तेदार किसी प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट में नहीं आ सकते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब संख्या एकाएक बढ़ जाए तो संदेह उठना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में विवाद कोई नई बात नहीं है। राज्य बनने के बाद 2003 में जो पहली परीक्षा हुई थी उसके परिणाम को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था। आयोग के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा था। आयोग के एक सदस्य तो लंबे समय तक फरार रहे। वह प्रकरण आज भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अब निर्णय उक्त भारतीयों के खिलाफ आ भी जाए तो क्या होगा? जो भर्तियां हुई थी वे नौकरी करते कई पदोन्नति पा चुके हैं। उन्हें अब पद से हटाया जाना संभव नहीं होगा। अगर उस समय योग्य उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी हुई भी तो उन्हें तो न्याय नहीं मिला। लोक सेवा आयोग जब युवा उम्मीदवारों के विश्वास पर खरा नहीं उतरे तो यह केवल किसी संस्था की साख का प्रश्न नहीं है बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 16 का सरासर उल्लंघन है। यह योग्यता को नकार देने वाली बात है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग पर संदेह उभरे हैं, उनका गंभीरता से निराकरण करे। हर विषय में राजनीतिक बयानबाजी ठीक नहीं है, कभी संदेह का निराकरण भी करना चाहिए। इसके लिए हाल में जारी परिणाम में जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, उनकी उत्तरपुस्तिकाओं को सार्वजनिक कर देना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार अपने और अन्य सफल उम्मीदवारों के उत्तरों को मिले अंकों को देख सके। ऐसा हुआ तो आरोप लगाने वालों का संदेह दूर होगा। अगर गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लोक सेवा आयोग पर लग रहे आरोपों से दुखी हैं, इसलिए संदेह को दूर करने कोई निर्णय लें जिससे आयोग पर युवा उम्मीदवारों का विश्वास बना रहे।

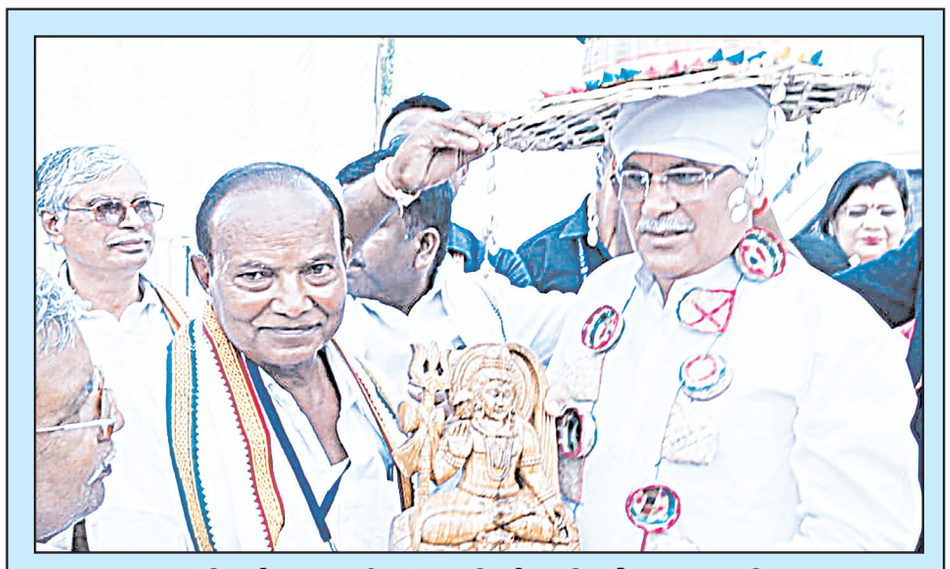

मुख्यमंत्री को पहनाई बांस की टोकरी और सूपा की माला

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के स्वागत में उन्हें बांस की टोकरी और सूपा की माला पहनाई गई। यह माला विशेष रूप से बनाई गई है, जिसमें बांस से बनी छोटी-छोटी सूपा, टुकनी का उपयोग किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को लकड़ी से बनी भगवान शंकर की प्रतिमा भेंट की गई।

2024 चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए प्रियंका का नाम

2024 लोकसभा चुनाव कई दल विपक्ष को एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ने की अपील कर चुके हैं। इन सब के बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर विपक्ष को 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को हराना है तो उसे एक ऐसा बड़ा चेहरा सामने लाना होगा जो लोकप्रिय, विश्वसनीय और स्वीकार्य हो। प्रियंका गांधी से अधिक लोकप्रिय, स्वीकार्य और विश्वसनीय कोई नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं विपक्षी दलों से उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित करने की अपील करना चाहता हूं। राहुल गांधी पर बोलते हुए आचार्य प्रमोद ने कहा कि वो इस समय तपस्वी की भूमिका में हैं। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज चाहिए। बूझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव पूरी तरह से चेहरे पर होगा।

ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सभी लोग बड़े नेता हैं पर एक क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने कहा कि आज मोदी पार्टी से बड़े हो चुके हैं। मोदी के खिलाफ चुनाव में कौन होगा, देश की जनता यह भी

जानना चाहती है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के रणनीति पर बड़ा बयान दिया था। ममता ने कहा कि जहां कहीं भी कांग्रेस मजबूत है, हम उसका समर्थन करेंगे। इसके साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि मजबूत क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

ऐसी बातें कहने से भ्रम पैदा होता है-सौगत

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने आचार्य प्रमोद के बयान पर कहा कि मैं प्रियंका गांधी के बारे में कुछ नहीं जानता। लोग कहते हैं कि वह इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं। उन्होंने कांग्रेस को अच्छा करने में मदद की। टीएमसी सांसद ने कहा कि हिमाचल और कर्नाटक के परिणाम में उनकी भूमिका बड़ी रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि वह कभी भी लोकसभा या विधानसभा सदस्य नहीं रही। ऐसी बातें कहने से भ्रम पैदा होता है। चीजों को गैर जिम्मेदाराना नहीं कहा जाना चाहिए। अपने बयान में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर विपक्ष को 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को हराना है तो उसे एक ऐसा बड़ा चेहरा सामने लाना होगा जो लोकप्रिय, विश्वसनीय और स्वीकार्य हो।

इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने साफ तौर पर कहा दिया कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी से अधिक लोकप्रिय, स्वीकार्य और विश्वसनीय कोई नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं विपक्षी दलों से उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित करने की अपील करना चाहता हूं। राहुल गांधी पर बोलते हुए आचार्य प्रमोद ने कहा कि वो इस समय तपस्वी की भूमिका में हैं। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज चाहिए। बूझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव पूरी तरह से चेहरे पर होगा।

प्रमुख समाचार

पायलट-गहलोत के घमासान पर खड़गे की पैनी नजर

नयी दिल्ली। राजस्थान कांग्रेस में खींचतान को लेकर पार्टी में अलग-अलग राय देखने को मिल रही हैं। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी खुलकर सीएम अशोक गहलोत के पक्ष में दिख रहे हैं। हालांकि, माना जा रहा है कि राजस्थान के घटनाक्रम पर आलाकमान की पैनी नजर है। दावा किया जा रहा कि कर्नाटक ने निपटने के बाद पार्टी राजस्थान मसले को सुलझाने की कोशिश करेगी। वहीं, राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने सचिन पायलट को मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घटनाक्रम से वाकिफ हैं और जल्द फैसला करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सचिन पायलट ने अपनी पांच दिन की जनसंघर्ष यात्रा के बाद सोमवार को एक जनसभा की थी। इस जनसभा के जरिए पायलट ने अपनी पार्टी के सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था। पायलट की विभिन्न मांगों पर निजामुद्दीन ने कहा कि घरों में यह प्रक्रियाएं सदा चलती रही हैं.

क्वाड बैठक रद्द, प्रधानमंत्री का आस्ट्रेलिया दौरा कीर्यक्रम यथावत

नयी दिल्ली। आस्ट्रेलिया में प्रस्तावित क्वाड बैठक के रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह अगले सप्ताह तय कार्यक्रम के अनुसार आस्ट्रेलिया की यात्रा पर जायेंगे। जानकार सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा देश में उत्पन्न गंभीर आर्थिक संकट पर ध्यान केंद्रित करने के मकसद से अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा को स्थगित करने के कारण सिडनी में प्रस्तावित क्वाड देशों के नेताओं की बैठक रद्द कर दी गई है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 समूह और क्वाड सहित तीन प्रमुख बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए शुक्रवार को जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की छह दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इसमें वे 22-24 मई तक आस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में मोदी 19 मई से 21 मई तक जापानी शहर हिरोशिमा का दौरा करेंग।

जाति सर्वेक्षण के लिए आर्टिकल 15-16 का हवाला

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल ने बुधवार को बिहार सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति करोल 6 फरवरी को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने कहा कि वह कुछ संबंधित मुकदमों में पक्षकार थे, जिन्हें पहले उच्च न्यायालय में सुना गया था। शीर्ष अदालत की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बीआर गवई भी शामिल थे, ने निर्देश दिया कि इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष एक उपयुक्त पीठ के गठन के लिए रखा जाए। उच्च न्यायालय के 4 मई के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर एक अपील में बिहार सरकार ने कहा कि स्थगन से पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अडानी के खिलाफ जांच 14 अगस्त तक पूरी होगी

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय

प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए बुधवार को 14 अगस्त तक का समय दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय की इस पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पारदीवाला भी हैं। पीठ ने अडानी मामले में न्यायमूर्ति ए एम सप्रे समिति की रिपोर्ट सभी पक्षकारों के साथ साझा करने का आदेश दिया ताकि वे इस मामले में अदालत की मदद कर सकें। यह रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी जा चुकी है।

इमरान के घर को लाहौर पुलिस ने घेरा

लाहौर। 9 मई के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर क्या करेंगे? इमरान खान के समर्थकों द्वारा सेना का जो हाल इन दिनों मुल्क में देखने को मिला वो पहले कभी नहीं हुआ था। अब लाहौर पुलिस ने इमरान खान के घर

को एक बार फिर घेरना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि इमरान खान के घर पर 30 से 40 आतंकवादी छुपे हुए हैं। मंत्री आमिर मीर ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि इमरान के घर में छुपे हैं 30-40 आतंकियों को छुपे हुए हैं। इसके साथ ही इमरान खान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। मंत्री आमिर मीर की तरफ से कहा गया कि 30-40 आतंकवादियों को या तो पुलिस के हवाले किया जाए या फिर कार्रवाई होगी। कार्यवाहक सूचना मंत्री आमिर मीर ने लाहौर में हा कि पीटीआई को इन आतंकवादियों को सौंप देना चाहिए या कानून अपना काम करेगा।

कांग्रेस, कुर्सी और कलह- सत्ता की मलाई पर दावेदारी की लड़ाई बेहद पुरानी

अभिनय आकाश

कर्नाटक के नतीजों के चार दिन बाद भी सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। 18 मई को निर्धारित शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कर्नाटक के लिए अपने मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है।

कर्नाटक में कहां फंसा है पेंच

पार्टी नेतृत्व दोनों नेताओं के बीच सत्ता साझा करने के लिए अलग-अलग फॉर्मूले पेश कर रहह है, जो राज्य में पार्टी की प्रभावशाली जीत के सूत्रधार थे। टर्म-शेयरिंग एक संभावित तरीका है, ऐसे में शिवकुमार अब सरकार में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन केपीसीसी प्रमुख के रूप में बने रहेंगे। कहा जा रहा है कि वो टर्म-शेयरिंग पर सार्वजनिक आश्वासन चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार डीके शिवकुमार ने पार्टी के सामने शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है कि सीएम के रूप में पहला हाफ टर्म उन्हें मिले। यानी जो शुरू का टेन्योर है वो शिवकुमार खुद के लिए चाहते हैं। उसके बाद का कार्यकाल सिद्धारमैया को दे दिया जाए। उन्होंने कहा है कि मैं चुपचाप रहूंगा। कुछ नहीं कहूंगा। सूत्रों के हवाले से इससे पहले ये भी बात सामने आई थी कि सिद्धारमैया कि तरफ से भी कुछ इसी तरह का दावा किया गया था। उन्होंने कहा था कि मेरी तो उम्र 75 साल हो गई है और पहले कार्यकाल मुझे दे दिया जाए। उसके बाद डीके शिवकुमार को बना दिया जाए। सूत्रों ने यह भी कहा कि आलाकमान भी राहुल गांधी से यह कहते हुए बंटा हुआ लगता है कि उन्हें

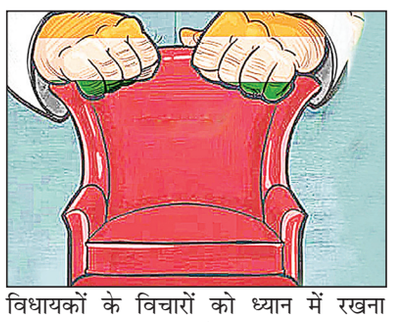

विधायकों के विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। पता चला है कि नवनिर्वाचित अधिकांश विधायकों ने सिद्धारमैया का समर्थन किया है। अन्य वरिष्ठ नेताओं का मानना ??है कि शिवकुमार को कांग्रेस की जीत के पीछे उनकी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। कम से कम एक नेता ने कहा कि खड़गे को भी "फाइटर्स" पसंद हैं। कुल मिलाकर कहें तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर कांग्रेस के सामने पशोपेश कि स्थिति है।

कलह की कहानियां फिर ताजा हुई

दिल्ली में पिछले तीन दिन से चल रही इस मैराथन मंथन के बीच रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया के सामने आकर साफ कर दिया की अभी फैसले में तीन दिन और लग सकते हैं। जिस तरह से विशाल जनादेश के बावजूद कांग्रेस में सीएम पद को लेकर किचकिच शुरू हुई है उसे देख कांग्रेस के अंदरखाने कलह की सारी कहानियां एक बार फिर ताजा हो गई। मिशाल छोड़कर देखा जाए तो कर्नाटक छोड़ तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। उसमें राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पालयट के बीच सियासी तलवारें खिची हुई हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच बड़ी मुश्किल से तूफान थमा है। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने प्रतिभा सिंह की चुनौती खड़ी है।

पहाड़ी राज्य हिमाचल का भी यही हाल

पिछले साल दिसंबर के महीने की बात है जब कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए तैयार दिख रही थी, तो मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार होने की वजह से पार्टी को समस्या का सामना करना पड़ा था। प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कह दिया था कि पार्टी में मुख्यमंत्री पद के कम से कम आठ दावेदार हैं। सीएम को लेकर कांग्रेस में परिणाम के बाद मंथन चल रही थी तो सुखविंदर सिंह सुखू, मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह इस दौड़ में आगे चल रहे थे।

हिमाचल पीसीसी प्रमुख और पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह पहली बार 2004 में मध्य हिमाचल के मंडी से महेश्वर सिंह को हराकर लोकसभा के लिए चुनी गई थीं। 2013 के उपचुनाव में, उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को उसी सीट से हराया था, जिसका प्रतिनिधित्व उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके पति करते थे। वह भाजपा के राम स्वरूप शर्मा की मृत्यु के बाद सांसद चुनी गईं। लेकिन पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इसकी प्रचार समिति के प्रमुख सुक्खू ने मध्य हिमाचल की नादौन सीट से चुनाव लड़ा था। पार्टी कैडर के बीच स्वीकार्यता वाले तीन बार के विधायक पर ही कांग्रेस ने भरोसा जताया और हिमाचल की कमान सौंपी।

भाजपाईयो ने अवैध शराब की बिक्री के विरोध में खरोरा थाने का किया घेराव

खरोरा। खरोरा तहसील में लगातार अवैध शराब बिक्री,शराब माफ़ियाओं की गुंडागर्दी से त्रस्त क्षेत्र की महिलाओं के साथ भाजपा ने खरोरा थाना का घेराव किया। हजारों की भीड़ थाने को घेर कर खड़ी थी वहीं पुलिस बल भी वांछनीय परिस्थिति से निपटने के लिये तैयार थी। लोगों का यह हुजूम तपती गर्मी में हाथ मे तख्ती लिए,महिलाओं की भीड़ यह दृश्य खरोरा थाने का है जहां भाजपा ने शराबबंदी और अवैध शराब बिक्री को लेकर मोर्चा खोला है दरअसल क्षेत्र की महिलाओं के अपने गांव में हो रहे खुलेआम अवैध शराब बिक्री से परेशानी है महिलाओं का कहना है छोटे बच्चे भी शराब में लिप्त हो गए हैं गली-गली दुकानों पर चौराहों पर अवैध शराब बिक रहे हैं जिससे बड़े बूढ़े नौजवान बच्चे सभी नशा खोर हो चुके हैं इस मामले को लेकर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने वेदराम मनहरे के नेतृत्व मे प्रशासन को ज्ञापन दिया था और एक उग्र आंदोलन की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी के

नेताओं का माने तो पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में कार्यवाही नहीं करती ऐसे में शराब माफ़ियाओं का मनमाना रवैया ग्रामीणों को परेशान कर रखा है। अवैध शराब बिक्री को लेकर महिलाएं किस कदर त्रस्त है।

क्षेत्र के बीजेपी नेताओं की माने तो लगातार कांग्रेस के लोग अवैध शराब माफ़िया के रूप में काम कर रहे हैं जिस तरह से गांव गांव शराब खुशियों का रेला लगा हुआ है भविष्य में यह खतरनाक हादसा बन सकता है छोटे बच्चों से लेकर नौजवान बूढ़ों तक शराब की लत से त्रस्त हैं कोई काम पर नहीं जाता किसी के घर खाने के लिए दो निवाले नहीं है महिलाओं बच्चों को पीट रहे हैं ऐसी स्थिति में सरकार को शराबबंदी कर ही देनी चाहिए नशा मुक्ति अभियान के प्रदेश प्रभारी वेदराम मन हरे का कहना है कि जिस तरह से सरकार शराब माफ़िया के रूप में काम कर रही है आने वाले समय में जनता उसे सत्ता से खींचकर उतारेगी। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने इस पूरे मामले को दिखावा कहते हुए प्रोपेगेंडा करार दिया और कहा जिस पार्टी के नेता खुद शराब खुशियों से अवैध वसूली में लिप्त है वह शराबबंदी की बात करती है यह अशोभनीय है।

इस अवसर पर नशा मुक्ति अभियान के प्रदेश प्रभारी वेदराम मनहरे ने कहा की यह आंदोलन अभी शुरुआत है अगर अवैध शराब बिक्री बंद नहीं हुई तो चक्का जाम किया जायेगा। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रदेश प्रभारी अंजय शुक्ला ने कहा की धरसींवा विधानसभा के अंतर्गत सभी थानो का यहीं हाल है अवैध शराब बिक्री खुले आम हो रहा है। वहीं उक्त विरोध प्रदर्शन मे हजारों लोग शामिल हुए,वहीं उसमे अधिकांश महिलाए थी और महिलाएओ ने एक सवार मे कहा अगर अवैध शराब बिक्री बंद नहीं हुई तो आगामी चुनाव मे कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेकेंगे।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष अभिनेश कश्यप,प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अंजय शुक्ला,नशा मुक्ति अभियान प्रदेश प्रभारी वेदराम मनहरे, नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल सोनी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत तिल्दा टिकेश्वर मनहरे, भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर, सरपंच संघ अध्यक्ष मिथलेश साहू, सरपंच विनोद देवांगन, मंजू हीरालाल वर्मा, , रजन पारधी, अशोक वर्मा, कचरा बाई दिलीप मार्कण्डेय राजू वर्मा, राजिपोर्ट दिलीप, तेजराम पाल, पंकज कुरे, सरजू साहू, जनपद सदस्य अरुण भारतद्वाज, पुरेन्द्र नायक, गोलू यादव, आयुष वर्मा, सुबोध सेन, अनिल सोनवानी, व अन्य मौजूद रहे।

सांसद मोहन मंडावी के पहल पर जनमुक्ति मोर्चा ने हर्ष जताया

बीईएमएल के ठेका श्रमिकों की समस्याओं का निदान करें बीएसपी प्रबंधन

■ 4 माह से भूख हड़ताल कर आंदोलन पर प्रबंधन उदासीन

दल्लीराजहरा। जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रति निधि मण्डल द्वारा बी.ई.एम.एल. के ठेका श्रमिकों की मजदूरी में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन और अधिकारियों की सह से किये जा रहे भ्रष्टाचार के निदान हेतु कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मण्डावी से मुलाकात कर उच्च स्तरीय जांच व समस्या के निदान करने के लिए मांगो से अवगत कराया गया व भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा विवाद उत्पन्न करने के लिए, प्रबंधन द्वारा घोषित ट्रेड यूनियन की भूमिका के बारे में बताया गया। तब सांसद महोदय द्वारा प्रबन्धन के अनैतिक कार्यो रोष व्यक्त करते हुए श्रम उपायुक्त रायपुर के आदेश 2019 को अभी तक क्रियान्वित नही करने पर रोष जताया गया और विगत 4 माह से भूख हड़ताल कर आंदोलन पर किसी प्रकार की पहल नही करने पर स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता पर रोष व्यक्त किया गया। सांसद मोहन मण्डावी ने दल्ली राजहरा माइंस में व्याप्त मजदूरों के शोषण व भ्रष्टाचार के विषय मे उप श्रमायुक्त रायपुर आर.के.पुरोहित को दूरभाष से आदेशित किये कि शीघ्र ही भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को बोलकर बी.ई.एम.एल.के ठेका श्रमिको की समस्याओ का निदान करें।

सांसद मोहन मण्डावी के इस सार्थक पहल से राजहरा के बी.ई.एम.एल. के ठेका श्रमिकों व अन्य ठेका श्रमिको को उम्मीद और खुशी जाहिर किये है व ठेका श्रमिकों द्वारा कहा गया है कि समय समय पर सांसद द्वारा इस प्रकार से ध्यान देने पर नियमित कर्मचारियों व ठेका श्रमिको के शोषण मे कमी आएगी।सांसद मोहन मण्डावी व प्रतिनिधि मंडल के बैठक के लिए स्थानीय सांसद प्रतिनिधि राजेश दसोड़े का विशेष योगदान रहा व बैठक मे उपस्थित रहे। प्रतिनिधि मंडल में जीत गुहा नियोगी अध्यक्ष, जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़, बसन्त रावटे सचिव जन मुक्ति मोर्चा, संजय सिंग बी.ई.एम.एल. प्रतिनिधि, किसन रावटे,भोला प्रजापति उपस्थित थे।

अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे तहसील इकाई के पटवारी

सक्ती। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर तहसील सक्ती, बाराद्वार, जैजैपुर, हसौद के तहसील इकाई पटवारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में लगातार शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों के संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर शासन स्तर को अवगत कराया जाता रहा है, वहीं मांगो पर विशेष ध्यान नहीं मिलने से संघ द्वारा हड़ताल का रास्ता अख्तियार किया जाता है, ऐसे ही राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा भी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हाल ही में ग्राम सचिव हड़ताल से वापस आए हैं, उनके हड़ताल पर रहने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं पटवारियों के हड़ताल से भी कहीं ना कहीं आम नागरिकों को परेसानी होने वाली है। पटवारियों के इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में उनकी मुख्य मांग है कि वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए ग्रेड पे 2800 किया जावे, राजस्व निरीक्षक पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किया जाए, संसाधन एवं नेट भत्ता दिया जाए, मंहगाई के अनुरूप स्टेशनरी भत्ता दिया जाए, अतिरिक्त प्रभार वाले हल्के के पटवारियों को मूल वेतन का 50प्रतिशत अतिरिक्त हल्का भत्ता प्रदान किया जावे, पटवारी भर्ती हेतु योग्यता स्नातक की जाए, मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त की जाए एवं बिना विभागीय जांच के प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज न कि जाए। अपनी इन 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ लामबंध होकर तहसील स्तर पर स्थानीय इकाइयों के माध्यम से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है, सक्ती में भी पटवारी संघ जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने आज से टेंट लगा बैठ गया है। इस अवसर पर राजस्व पटवारी संघ शाखा सक्ती के अध्यक्ष प्रमोद चंद्रा, संरक्षक सत्यनारायण राठौर, हेमंत देवांगन, जय देवांगन, बाराद्वार अध्यक्ष मनहरण राठौर, जैजैपुर अध्यक्ष प्रमोद यादव, हसौद अध्यक्ष छत्रपाल सहित वरिष्ठ पटवारी अमित त्रिपाठी, विनय पटेल, हरिशंकर, रामेंद्र, महेंद्र, नमेंद्र, सुनील, रामकुमार, राहुल, कुंजन, जवाहर, मेहुल, भूपेंद्र बरेठ, सब्बीर, सुनीता राठिया, हेमलता, गीता, विनोद खांडे सहित पटवारी उपस्थित थे।

चांपा का वार्ड क्रमांक 14 सबरिया डेरा में, पानी के लिए मचा हाहाकार

चांपा। कोसा, कांसा और कंचन से अपनी पहचान रखने वाला चांपा अब करप्शन, कमीशन और कमिटमेंट तक सिमटकर रह गया है, नगरवासी जनहित के मुद्दों को लेकर नगरपालिका पहुंचते हैं जहां उन्हें कमिटमेंट के अलावा कुछ भी नही मिलता देखवाते हैं, बात करते हैं, करवाते हैं ये सब प्रचलित शब्द है। गौरतलब है कि एक तरफ तो नगर में पानी की तरह पैसा विकास कार्य के नाम से बहाया जा रहा मगर जिस स्थान पर वास्तव में जरूरत है वहां का काम नही हो रहा और नगरवासी परेशान हैं। वार्ड पार्षदों को भी बस अपने कमीशन की पड़ी है इसके अलावा जनहित के कामों के लिए उनके पास समय ही नहीं है। वार्ड नंबर 15 का सबरिया डेरा जहां लगभग 80 परिवार के 400 लोग निवास करते हैं, यह इलाका भी इन दिनों अपनी परेशानियों से सुर्खियां बटोर रहा है, वहां जीतने भी हैंडपंप है सब बंद है या गंदा पानी निकल रहा है जिससे लोगों में बीमारी फैलने का भी डर लगा रहता है। महिलाएं 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाती हैं तब कहीं परिवार चल रहा है। इनकी परेशानी वार्ड पार्षद को और न ही किसी अन्य जनप्रतिनिधि को नजर आई जिससे नाराज रहवासी आज मुख्य नगरपालिका अधिकारी से मिलने बड़ी संख्या में नगरपालिका पहुंचे जहां लेकिन वे मिले नहीं फिर सभी ने नगरपालिका के इंजीनियर दुबे से मिलकर अपनी सभी समस्याओं को बताया तथा शीघ्र ही पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। जिस पर दुबे जी ने सीएमओ से बात कर शीघ्र ही समाधान निकालने की बात कही। संतोष अनंत, पार्षद वार्ड नंबर 14 चांपा का कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए कई बार नगरपालिका मे मैं खुद भी आवेदन दिया हूं बात भी किया हूं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए है।

फुटपाथ में दुकानदारों का कब्जा शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ी

कोरबा। शहर में व्यवस्थित आवागमन के लिए जगह-जगह तैयार फुटपाथ में दुकानदारों ने कब्जा जमा रखा है। दुकान लगाने के लिए बनाए गए पौनी पसारी में व्यवसायी बाजार से दूर होने के कारण जाना नहीं चाहते। ऐसे में पैदल चलने वाले राहगीरों को सड़क में भरी ट्रैफिक के बीच आवागमन करना पड़ रहा है।

सड़कों में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पैदल चलकर बाजार पहुंचने वालों की सुविधा के लिए शहर के बुधवारी मार्ग में निगम प्रशासन ने साल भर पहले फुटपाथ का निर्माण किया। इसका उपयोग राहगीर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां लघु व्यवसाइयों ने डेरा जमा लिया है। सुबह होते ही पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े कारोबारी अपना दुकान लगाना शुरू कर देते हैं। कुम्हार, बंसोड़ जैसे व्यवसाइयों के लिए पौनी पसारी का निर्माण बुधवारी बाजार के दूसरे छोर में कांप्लेक्स के पीछे किया गया है। 23 लाख की लागत से निर्मित पौनी पसारी का अब तक एक बार भी उपयोग नहीं हुआ। बताना होगा कि फुटपाथ निर्माण के बाद यातायात विभाग कार्रवाई करती है और उस वक्त व्यवसायी वहां से हट जाते हैं। दो-तीन दिन बाद फिर से कब्जा जमा लेते हैं। कमोबेश यह दशा केवल बुधवारी मार्ग में ही नहीं बल्कि घंटाघर और कोसाबाड़ी चौक में भी बनी हुई है। निर्मला स्कूल के सामने बना फुटपाथ सब्जी दुकान संचालकों के कब्जे में है। यहां लगने वाली दैनिक हटरी सड़क पर चल रही है। स्कूल की छुट्टी के दौरान वाहनों का आवागमन थम जाता है। मार्ग को स्थाई रूप से राहगीरों के लिए खाली कराने की पहल यातायात विभाग ने नहीं की है। प्रमुख रूप से इसके लिए नगर निगम प्रशासन जवाबदार है नियमित निगरानी के लिए अतिक्रमण हटाओ दस्ता तैयार किया गया है। यह टीम केवल अवैध कब्जे तोड़ने पहुंचती है। फुटपाथ पर कब्जे पर सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने से न केवल शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही बल्कि सुंदरीकरण पर भी ग्रहण लग रहा। व्यवस्था बनाने बनाने के लिए निगम ने करोड़ों रूपये का निर्माण कार्य करा लिया है पर इसे अमली जामा पहनाने में असफल है। विडंबना यह भी है कि व्यस्ततम मार्ग होने के बाद भी बुधवारी मार्ग को भारी वाहनों से निजात नहीं दिलाई जा सकी है। बाजार के निकट रेलवे फाटक हर दो घंटे बंद हो जाती हैं। इससे बाजार मार्ग में भारी वाहनों की कतार लगी रहती है। कोरोना काल के बाद बुधवारी बाजार अब दैनिक हटरी में तब्दील हो चुकी है। यहां दैनिक सामान की खरीदी करने के लिए लोगों का दिन भर आना-जाना लगा रहता हैं। भारी वाहनों के व्यस्त आवागमन के बीच लोगों को यहां जान जोखिम में डाल कर खरीदारी करने आना पड़ता है।

वैवाहिक सीजन होने कारण शहर के सड़क में मई माह के शुरूआत से भीड़ देखी जा रही है। सामानों को खपाने की होड़ में व्यवसाइयों ने फुटपाथ तक सामग्री फैला रखा है। खासकर इलेक्ट्रानिक, बर्तन, होजियरी दुकान संचालकों ने सड़क तक सामान रख देते हैं। ऐसे में पैदल चलने वालों का सड़क पर चलना पड़ रहा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

तेंदूपत्ता तोड़ने जंगल गए अधेड़ पर भालू ने किया हमला

कोरबा। जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लाक अंतर्गत डोंगरतराई से लगे जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ने गए अधेड़ पर भालू ने हमला कर दिया। घायल को संजीवनी 108 टीम ने त्वरित उपचार और हास्पिटल पहुंचाकर जान बचाई। जानकारी के अनुसार ग्राम डोंगरतराई निवासी कंवल सिंह ओडे 50 वर्ष अपने गांव से ही लगे जंगल में अपने दोस्तों के साथ तेंदूपत्ता तोड़ने गया हुआ था। इसी दौरान अचानक एक भालू ने उस पर हमला कर दिया। युवक की तकरीबन पांच मिनट तक भालू से भिड़ंत होती रही, इसके बाद शोर शराबा और अन्य लोगों को पास आता देख भालू भाग गया। हमले में युवक के हाथ, जांघ में गहरी चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही पायलट श्रीपाल साहू और ईएमटी आनंद कुमार विश्वकर्मा तुरंत गांव पहुंचे और घायल कंवल का उपचार करते हुए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा लेकर आएं।

दंतैल हाथी ने पहले पटका फिर कुचला

बालोद। प्रदेश के कुछ जिलों में आए दिन कभी भालू तो कभी दंतैल हाथी जैसे जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। वहीं ये जानवार आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। इनके आंतक का कहर ऐसा है जहां लोगों को अपनी जान तक गवांनी पड़ रही है। ताजा मामला बालोद का है, जहां एक दंतैल हाथी ने 60 वर्षीय महिला की जान ले ली। दरअसल, जानकारी के अनुसार जिले में एक दंतैल हाथी का आतंक जारी है। दंतैल हाथी ने एक 60 वर्षीय महिला को मौत के घाट उतार दिया है। मंगलवार आज सुबह करीब 5 बजे गांव के तालाब किनारे शौच करने गई महिला को दंतैल हाथी ने सूंड से उठाकर फेंका और पैरों से भी कुचला। महिला का नाम गीता बाई ठाकुर बताया जा रहा है। ये पूरी घटना डौंडी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुंजकन्हार की है। मृतिका के पति का नाम अरुण कुमार है और कुंजकन्हार उसका मायका है, ससुराल कांकेर जिले का ग्राम पोड है।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने सड़को पर उतरी महिला कमांडो

बालोद। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ जितेंद्र यादव के मार्गदर्शन में एवं सहयोगी जन कल्याण समिति गुंदरदेही के सहयोग से महिला कमांडो का एक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने कार्यक्रम का आयोजन सहयोगीजन समिति गुरुहरडेही के कार्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने महिला कमांडो के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं आज बहुत जागरूक हो गई हैं। हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं देश विदेश में भी अपने काम के जरिए देश का नाम ऊंचा कर रही है। उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में हो रहे अपराध की जानकारी देते हुए सचेत रहने व लोगों को सचेत करने की बात कही। सड़क दुर्घटना को रोकने लोगों को यातायात नियमों का पालन करते हुए पहले, हेलमेट पहनने पर जन जागरुकता लाने की बात कही। समिति की अध्यक्ष शमशाद बेगम ने कहां की महिला कमांडो लगातार जन जागरूकता का कार्य कर रही हैं पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव की सुरक्षा व्यवस्था में भी लगी हुई हैं।

सीआईएसएफ जवान पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

दल्लीराजहरा। सीआईएसएफजवानों से मारपीट करने वाले फरार चोरों में से 2 को राजहरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। इसके पूर्व चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रार्थी सीआईएसएफ आरक्षक शंकु सुरेश अपने साथी आरक्षक नोहर लाल के साथ मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 जे 3288 से अपनी ड्यूटी पर पेट्रोलिंग करने राजहरा माइंस एरिया निकले थे सुबह करीबन 6-7 बजे राजहरा माइंस स्क्रैप यार्ड में 7-8 आरोपीगण लोहा चोरी कर रहे थे जिसे सीआईएसएफ के कर्मचारियों द्वारा आवाज देने पर आरोपीगण वार्ड क्रमांक 2 पंडरदल्ली तरफ भाग गये। तलाश करने पर सभी आरोपीगण शंकर सुरेन्द्र के घर के पास मिले जिसे सुरक्षाकर्मियों द्वारा माइंस में चोरी करने के लिये क्यों घुसे थे पूछने पर सभी आरोपीगण जान से मारने की धमकी दिए। वहीं आरोपी शंकर सुरेन्द्र ने चाकू से सुरक्षाकर्मी शंकु सुरेश के पीठ पर प्राण घातक हमला कर दिया जिससे दोनो सुरक्षाकर्मी अपनी जान बचाने के लिये अपनी मोटर सायकल को छोड़कर थाना आये।

बांगो बांध का जलस्तर 6.16 मीटर गिरा

कोरबा। बांगो बांध का जल स्तर मानसून आगमन से अब तक 6.16 मीटर गिरा है। इसकी पूर्ण भराव क्षमता 369.66 मीटर हैए जो कम होकर 352.50 मीटर हो गया है। वर्तमान में बांध में कुल भराव का 61 प्रतिशत भराव शेष है, जो बीते वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल माह में हुई वर्षा की वजह से इस बार ग्रीष्म फसल के लिए पानी देने की नौबत कम आई है। बांगो बांध के पानी का सिंचाई के लिए उपयोग बीते वर्ष की तुलना में कम हुआ है। किसानों इस बार धान की फसल कम लगाई है। ऐसे में नहर से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की आवश्यकता बहुत कम पड़ी। बायीं तट नहर को बंद किया जा चुका है। दायीं तट नहर से अभी 1750 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से सिंचाईए निस्तारी और उद्योगों को पानी देने के अलावा गर्मी के कारण जल स्तर में कमी आती है। इस बार मार्च माह से शुरू हुई गर्मी के बाद 1.43 मीटर पानी तापमान की भेंट चढ़ गई। बीते पांच वर्षों के भीतर मई माह शुरूआत में जल स्तर पर गौर किया जाए तो वर्ष 2019 में 351.40 मीटर था।

माँ अपने आप में पूर्ण संस्कारवान, मनुष्यत्व व सरलता के गुणों का सागर है : रंजना साहू

■ मातृ दिवस मनाने का मूल उद्देश्य समस्त माताओं को सम्मान देना है: काजल गोलछा

धमतरी। मातृ दिवस विशेष पर हेल्प एंड सर्व फाउंडेशन धमतरी के द्वारा माताओं को नमन करने जिनके आंचल में पले बढ़े उनका सम्मान करने हैप्पी मदर्स डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हेल्प एंड सर्व फाउंडेशन के द्वारा सर्वप्रथम माताओं का सम्मान करते हुए पांव छूकर आशीर्वाद लिए।

इस कार्यक्रम में विधायक रंजना साहू भी उपस्थित हुई, सर्वप्रथम विधायक ने वरिष्ठ गणमान्य माताओं का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिए और माताओं एवं बच्चों की उपस्थिति में विधायक रंजना साहू ने कहा कि हम एक शब्द है तो मां पूरी भाषा है, मां शब्द को परिभाषित कर पाना मुश्किल है, जीवन का सबसे सुखमय स्थान कोई जगह है तो वह सिर्फ मां का आंचल है। माँ के शब्द में वह आत्मीयता एवं मिठास छिपी हुई होती है, जो अन्य किसी शब्दों में नहीं होती। इसका अनुभव भी एक माँ ही कर सकती है। माँ अपने आप में पूर्ण संस्कारवान, मनुष्यत्व व सरलता के गुणों का सागर है। श्रीमती साहू ने प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्दों को याद कर बताया कि जब मैं पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, वो एकमात्र ऐसा दिन था मेरे जीवन का, जब मैं रो रहा था और मेरी माँ के चेहरे पर एक सन्तोषजनक मुस्कान थी। विधायक ने कहा कि जब हमारा जन्म हुआ वह पल हमें याद नहीं पर मां के आंचल का प्यार स्नेह आशीर्वाद वह धन है जो सदैव अपने बच्चों के खुशहाली की कामना करती है।

हेल्प एंड सर्व फाउंडेशन के प्रमुख काजल गोलछा ने बताया कि यह कार्यक्रम उन सभी मातृ शक्तियों को नमन है जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के सुख समृद्धि खुशहाली के लिए अर्पण किए हैं। मातृ दिवसा् मनाने का मूल उद्देश्य समस्त माताओं को सम्मान देना और एक शिशु के उत्थान में उनकी महान् भूमिका को नमन करना है। इस अवसर पर कार्यक्रम में सुशीला नाहर, डॉक्टर वर्षा, सरिता राखेचा, तिलम बड़ड़िया, सुशीला गोलछा, संजू बड़जातिया, मंजू बड़ड़िया, ममता संकखेलचा, विक्की बोहरा, केतन जसूजा, दिव्यांश जैन, निधिश जैन, अंजली बैद, मोनिका जैन, पूजा जैन, मुस्कान भंसाली, वरुण जैन, दर्शन जैन, चारु डागा, वेदिका, किट्ठू, स्नेहा डागा आदि उपस्थित रहे।

अमृत नाग किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नियुक्त

नगरी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा के सहमति, प्रभारी महासचिव पी.एल. पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ शासन, मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हरी गोविन्द सिंह तिवारी छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस प्रभारी, अमरजीत सिंह चावला प्रभारी महामंत्री (संगठन) एवं सुमित्रा धृतलहरे प्रभारी महामंत्री मोर्चा प्रकोष्ठ की अनुमति, प्रदेश अध्यक्ष रामबिलास साहू के अनुशंसा पर वरिष्ठ कांग्रेसी अमृत लाल नाग को छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है।

प्रदेश महामंत्री पद पर नियुक्ति के लिए अमृत नाग ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस रामबिलास साहू, एवं सिहावा विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही संगठन को मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करेंगे।

अमृत लाल नाग को छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर सिहावा विधायक डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, दिव्यांग जन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी, पूर्व विधायक अंबिका मरकाम, पीसीसी सदस्य लखन लाल ध्रुव, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद लोहाना, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगरी के अध्यक्ष भूषण साहू, मंडी सदस्य राजेन्द्र सोनी, विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रताप नाग, वरिष्ठ कांग्रेसी उत्तम गोलछा,किशन मगेंद्र कैलाश नाथ प्रजापति, रवि ठाकुर, अखिलेश दुबे, डिहू राम साहू, करण चंद्राकर, नारद साहू, भानेंद्र ठाकुर, मनोज साक्षी,मीना बंजारे, उमेश देव, छवि ठाकुर, अख्तर खान, नारद ध्रुव, अव्यूब खान, राजेन्द्र ठाकुर, टेश्वर ध्रुव, आसिफ खान, भरत निर्मलकर, नरेश छैदेहा, पेमन स्वर्णकार, सचिन भंसाली, अनवर रजा, सविता सोन, नंदिनी कंचन, विमला मरकाम, नीरज साहू, सोनू चौहान, महेंद्र पाण्डेय, प्रदीप सोन, तेजेंद्र भट्ठ, नदीम अली, आदित्य ठाकुर सहित क्षेत्र के कांग्रेस जनों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मणिपुर का आकलन करने के लिए पर्यवेक्षक भेजेगी कांग्रेस

नईदिल्ली। हिंसा से प्रभावित मणिपुर में स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने बुधवार को राज्य में जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षकों को भेजने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार शाम पार्टी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया। खड़गे ने ट्विटर पर कहा कि मणिपुर कांग्रेस के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुझे उन जबरदस्त कठिनाइयों से अवगत कराया, जिनसे मणिपुर के लोगों को इस मुश्किल समय में गुजरना पड़ा। जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षकों की एक टीम जल्द ही भेजी जा रही है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण और बेहद चिंताजनक है। खरगे ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य में स्थिति सामान्य होते देखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। शांति सुनिश्चित करने में हर समुदाय की हिस्सेदारी है। आइए हम सभी को विश्वास में लें। कांग्रेस ने राज्य में हिंसा के बाद मणिपुर में स्थिति को नियंत्रित करने में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका की आलोचना की है।

कांग्रेस के तंज पर भाजपा का उसी अंदाज में पलटवार

नई दिल्ली। अदाणी के साथ लिंक कर पीएम मोदी की तस्वीर शेयर करने के कांग्रेस के तंज के बाद भाजपा भी कहां चुप रहने वाली थी। भाजपा के ट्विटर हैंडल से भी पीएम पर कसे गए तंज का उसी अंदाज में जवाब दिया गया। इस बार बारी थी राहुल गांधी को निशाने पर लेकर उनपर तंज कसने की। भाजपा ने भी इस मामले में कांग्रेस की ही राह चुनी। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की जिसमें राहुल के आसपास उनके परिवार के लोगों की तस्वीरें दिख रही हैं। इन तस्वीर को शेयर कर भाजपा ने कांग्रेस के परिवारवाद पर निशाना साधा है। राहुल के आसपास की तस्वीरों में देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन की तस्वीर भी है। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीर को कैप्शन दिया है, इनकी दुनिया। भाजपा और कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया में जारी इस आरोप-प्रत्यारोप के बाद दोनों पार्टियों के समर्थक भी अपनी कलात्मकता दिखाने से बाज नहीं आ रहे।

मायावती ने आज बसपा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाने और सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी मशीनरी व धर्म के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए 18 मई को लखनऊ में पार्टी के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। मायावती ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी द्वारा जनविरोधी नीतियों, गलत कार्यकलापों के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल अति-गंभीर व अति-चिंताजनक है। यह लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, इन घोर जनविरोधी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने के लिए ठोस रणनीति बनाकर उसके हिसाब से आगे बढ़ने, खासकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों, मंडल व जिला अध्यक्षों आदि की लखनऊ में बृहस्पतिवार को विशेष बैठक बुलाई है।

शिवसेना-यूबीटी ने किया भाजपा पर वार

मुंबई। महाराष्ट्र में बीते दिनों कई धार्मिक दंगे हुए हैं। इसको लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए मुख्यमंत्री शिंदे और गृहमंत्री फडणवीस की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का दंगे भड़का कर राजनीतिक रोटियां सेंकने का धंधा पीढ़ियों से चला आ रहा है और चुनाव नजदीक आते ही इस धंधे के निवेश में बढ़ोतरी की जाती है। शिवसेना (उद्धव गुट) ने कहा कि राज्य के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वे उन लोगों से घिरे हुए हैं, जो संविधान, राष्ट्रीय एकता और धार्मिक भावना को दरकिनार कर सत्ता पाने की लालसा रखते हैं। सामना में कहा कि राज्य की जनता को महाराष्ट्र के हित के लिए सावधान रहना होगा। महाराष्ट्र में दंगों की प्रयोगशाला खोलकर भाजपा और उसके समर्थक सामाजिक समरसता को बिगाड़कर मतों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहता है यूरोपीय संघ

नईदिल्ली। जहां यूरोप के देश रूस से प्रतिबंधों के कारण तेल नहीं खरीद पा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी विदेश नीति के कारण प्रतिबंधों के बावजूद भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा हैं। यूरोप के कई देश लगातार प्रतिबंदों के बावजूद रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर सेंशन्स लगाने की मांग करते रहे हैं। यह मांग एक बार फिर उठी और भारत ने इस तरह की नाजायज मांग का यूरोप को करारा जवाब दिया है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल को यूरोपीय संघ परिषद के नियमों पर एक नज़र डालने की सलाह दी। बोरेल ने पहले कहा था कि यूरोपीय संघ को पश्चिमी देशों के रूप में यूरोप में डीजल सहित परिष्कृत ईंधन के रूप में रूसी तेल को फिर से बेचने पर भारत पर कार्रवाई करनी चाहिए।

कांग्रेस में मंथन जारी, सिद्धरमैया के गांव में जश्न का माहौल

शिवकुमार ने उपमुख्यमंत्री बनने से किया इनकार

नईदिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस में विधायक दल का नेता और मुख्यमंत्री पद के लिए रार जारी है। कर्नाटक का नेतृत्व कौन करेगा- सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार? सिद्धारमैया के कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के समर्थकों ने उनके पोस्टर पर दूध उड़ेल कर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डीके शिवकुमार ने किसी भी शर्त पर बातचीत करने का विरोध किया है। उन्होंने असहमति जताई। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने भी उपमुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है। बुधवार को राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के आवास पर सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों से मुलाकात की। पार्टी कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री की आधिकारिक घोषणा शाम तक कर सकती है। कांग्रेस नेतृत्व ने मंगलवार को नई दिल्ली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार से मुलाकात की। बुधवार को राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के आवास पर सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों से मुलाकात की। इस बीच, कर्नाटक के सीएम पद पर फैसले से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के समर्थकों ने जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। रणदीप सुरजेवाला ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि सिद्धारमैया को एक बार फिर मुख्यमंत्री नामित किया जा सकता है। कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी फुरसत की पार्टी है, पांच साल तक पार्टी में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर राहुल गांधी से दोनों नेताओं की मुलाकात को मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सिद्धरमैया ने करीब आधे घंटे तक राहुल गांधी के साथ चर्चा की तो शिवकुमार ने उनसे एक घंटे से अधिक देर तक बातचीत की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शिवकुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंचे। सिद्धरमैया और शिवकुमार दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, हालांकि सिद्धरमैया को इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। इससे पहले कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस में मंगलवार को भी गहन मंथन जारी रहा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले राहुल गांधी के साथ चर्चा की तथा फिर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे दोनों नेताओं सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार से मुलाकात की थी।

: कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए नयी दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के बीच गहन विचार विमर्श का दौर अभी भी जारी है लेकिन सिद्धरमैया के नाम पर मोहर लगने की कुछ मीडिया रिपोर्टों के साथ ही उनके पैतृक गांव और बेंगलुरु में उनके निवास के बाहर जश्न का माहौल बन गया है। कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर बुधवार या बृहस्पतिवार तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है तथा अगले 48 से 72 घंटों के अंदर राज्य में नया मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ जाएगा। उससे पहले बेंगलुरु में विधानसभा में विपक्ष के निवर्तमान नेता सिद्धरमैया के सरकारी आवास के बाहर जुटे उनके समर्थकों के बीच खुशी का माहौल है क्योंकि कुछ मीडिया संगठनों ने दावा किया है कि उनके नाम पर मुहर लग गयी है और केवल आधिकारिक घोषणा होना बाकी है।

अपने नेता की तस्वीर लिये वे सिद्धरमैया की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। इन समर्थकों ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के निवास के बाहर रखी गई आदमकद तस्वीर पर दूध चढ़ाया। । उनके गृह जिले मैसुरू तथा पैतृक गांव सिद्दारमनाहुंडी में भी ऐसा ही नजारा था। उनके समर्थकों एवं शुभचिंतकों ने पटाखे छोड़े, नृत्य किया, मिठाइयां बांटी और सड़क पर लगाई गई तस्वीर पर दूध चढ़ाया।

सुप्रीम कोर्ट ने शिवकुमार को दी राहत तो सीबीआई को लगा झटका

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में जांच पर अंतरिम रोक से संबंधित कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने शिवकुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी के यह कहने के बाद मामले को स्थगित कर दिया कि मामले में 23 मई को उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बाद में अलग-अलग तारीखों पर रोक को और बढ़ा दिया गया। आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के खिलाफ छापा मारा था, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने बाद में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी। मंजूरी 25 सितंबर, 2019 को मिली और तीन अक्टूबर, 2020 को शिवकुमार पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। शिवकुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया और अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मंजूरी एवं कार्रवाई को चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें बार-बार नोटिस जारी करके उन पर मानसिक दबाव बना रही थी जबकि मामला 2020 का है।

मोदी के नेतृत्व में भारत ने देखा परिवर्तन : जेपी नड्डा

मुंबई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को मुबंई दौरे पर थे। मुबंई में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुंबई में लभार्थी सम्मेलन को नड्डा ने संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि योजनाएं पहले भी बनती थीं, नीतियां पहले भी बनती थीं, लेकिन वह अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थीं। उन्होंने कहा कि पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसा न जाने कहां चला जाता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करोड़ों रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक खाते में भेजे गए।

नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले लगभग करोड़ों बहनें लकड़ी का चूल्हा जलाती थीं, आज उज्ज्वला योजना के तहत 9.60 करोड़ से अधिक महिलाओं को निशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के विपरीत, भाजपा ने हमेशा लोगों के जीवन में अंतिम छोर तक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि साथ ही कांग्रेस की कमीशन सरकार के विपरीत हमारी सरकार ने हजारों करोड़ सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, भारत की मुद्रास्फीति दर नियंत्रण में है और जीडीपी तेज गति से बढ़ रही है।

भाजपा अद्यक्ष ने दावा किया कि पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व में, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जिसने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक हम पर शासन किया था! उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने महान परिवर्तन देखा है। उन्होंने कहा कि शीर्ष ऑटोमोबाइल निर्माता देशों में शामिल होने से लेकर दुनिया के सबसे सफल कोविड टीकाकरण अभियान तक भारत ने एक लंबा सफर तय किया है।

योगी के नेतृत्व में चुनाव में भाजपा ने रचा इतिहास

लखनऊ। नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने आमजन से भाजपा का महापौर जिताने के साथ ही बोर्ड भी बनवाने की अपील की थी। सीएम के इस आह्वान पर जनता ने मुहर लगाई, जिससे पहली बार 13 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बोर्ड बनाएगी। नवसृजित शाहजहांपुर और बुंदेलखंड के झांसी में योगी की अपील का यह असर रहा कि समाजवादी पार्टी के एक भी पार्षद नहीं जीते। सपा इन दोनों नगर निगमों में शून्य पर रही। वहीं कई नगर निगम क्षेत्रों में सपा से अधिक जनता ने निर्दलियों पर भरोसा जताया। कानपुर, वाराणसी व बरेली में बसपा और अयोध्या-सहारनपुर में पार्षद पद पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला।

सूबे के 17 नगर निगमों में से 13 पर भारतीय जनता पार्टी के आधे से अधिक पार्षदों ने जीत हासिल की। लखनऊ व कानपुर में 110-110 सीटों में से क्रमशः 80-63 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते। वहीं वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज व आगरा के 100-100 में से क्रमशः 63, 66, 56 व 58 सीटों पर कमल खिला। वहीं गोरखपुर व बरेली की 80-80 सीटों पर भाजपा क्रमशः 42 व 51 पर जीती। भाजपा की यह जीत सीएम योगी के विश्वास की जीत है। जनता का सीएम पर यह विश्वास है कि उनके एक आह्वान पर हर जगह कमल खिल गया।

खेल
प्रमुख समाचार

बेंगलोर को आज हैदराबाद के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी

हैदराबाद। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) की टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 में गुरुवार को यहां जब सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ अहम मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजरें प्लेऑफ में जगह बनाने के साथ भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली के प्रदर्शन पर होगी। आरसीबी इस समय 12 मैचों में इतने ही अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। उसे प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। एसआरएच के नाम 12 मैचों में आठ अंक है और टीम खिताब की दौड़ से बाहर हो गयी है। कप्तान फाफ डुप्लेसी के साथ कोहली आरसीबी के लिए इस सत्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं, लेकिन लगातार दो मैचों में विफलता (राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 18 और मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक रन) के बाद यह दिग्गज खिलाड़ी एसआरएच के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने की कोशिश करेगा।

डुप्लेसी 12 मैचों में 57.36 के औसत से 631 रन के साथ मौजूदा सत्र में अब तक लीग के शीर्ष स्कोरर है। कोहली इस मामले में टीम के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज है। उन्होंने 39.81 की औसत और छह अर्धशतकों की मदद से 438 रन बनाये है। कोहली की बल्लेबाजी में हालांकि निरंतरता की कमी रही है और वह तेजी से रन बनाने के मामले में जूझते दिखे है। इन दोनों के अलावा टीम को ग्लेन मैक्सवेल से भी काफी उम्मीद होगी। मैक्सवेल ने मौजूदा सत्र में पांच अर्धशतकीय पारियां खेली है। इन तीनों के अलावा टीम के अन्य बल्लेबाज लगातार अच्छा करने में विफल रहे है। टीम पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 112 रन की बड़ी जीत दर्ज करने के बाद आत्मविश्वास से भरी होगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 372 अंक टूटा निफ्टी 18,200 के नीचे

नईदिल्ली। भारतीय शेयर मार्केट में बुधवार यानी 17 मई को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 371.83 अंक टूटकर 61,560.64 अंक पर और निफ्टी 104.75 अंक के नुकसान से 18,181.75 अंक पर बंद हुए। शेयर बाजार में दूसरे दिन भी गिरावट जारी रही। मंगलवार को भी बीएसई सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 61,932 पर और निफ्टी 112 अंक फिसलकर 18,286 पर बंद हुए थे। हालांकि, व्यापक बाजारों ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में 0.6 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। स्टॉक की बात करें तो, रेडिंगटन 6 फीसदी डूब गया क्योंकि इसका त्त्र प्रॉफिट 10 फीसदी घटकर 310 करोड़ रुपये रह गया। मार्च तिमाही के नतीजों के बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। सेक्टर के लिहाज से निफ्टी आईटी, मेटल, रियल्टी इंडेक्स आज के टॉप लूजर रहे।

2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी

नईदिल्ली। घरेलू मांग मजबूत रहने से भारतीय इकोनॉमी के 2024 के कैलेंडर साल में 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। हालांकि, इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंची ब्याज दरों तथा कमजोर बाहरी मांग से इस साल देश का निवेश और निर्यात प्रभावित होगा। संयुक्त राष्ट्र की '2023 के मध्य तक वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं' शीर्षक वाली रिपोर्ट मंगलवार को यहां जारी की गई। रिपोर्ट कहती है कि भारत, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2023 में 5.8 प्रतिशत और 2024 (कैलेंडर वर्ष आधार) में 6.7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत घरेलू मांग से समर्थन मिलेगा। हालांकि, ऊंची ब्याज दरों और कमजोर बाहरी मांग से 2023 में देश के निवेश और निर्यात पर दबाव बना रहेगा।

जोमैटो ने आईसीआईसीआई के साथ पार्टनरशिप में पेश की यूपीआई पेमेंट सर्विस

नईदिल्ली। खाने-पीना का सामान ऑनलाइन ऑर्डर के जरिये डिलीवर करने वाली जोमैटो भारत में अपने कुछ यूजर्स के लिए यूपीआई सेवाओं की पेशकश करने वाला पहला ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी ऐप बन गया है। जोमैटो ने सेवा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। इसके साथ ही जोमैटो अपने यूजर्स के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के लिए थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर के रूप में लाइव हो गया है। जोमैटो ने कहा कि उसने जोमैटो यूपीआई नामक अपना यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) पेश कर दिया है। गुरुग्राम स्थित कंपनी जोमैटो ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी के बाद यूपीआई को लॉन्च किया है। बता दें कि यूजर्स को बेहतर सर्विस देने के उद्देश्य से जोमैटो के यूपीआई लॉन्च किया गई।

अगले महीने लॉन्च होने वाला है ऐपल का आईओएस 17

नईदिल्ली। टेक जाइंट ऐपल अगले महीने यानी जून में होने वाली वर्ल्डवाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस (डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी) में अपना अपकमिंग आईओएस 17 सॉफ्टवेयर वर्जन पेश करने वाला है। बता दें कि डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी 5 जून को होगा। हालांकि, इवेंट से पहले ही ऐपल के नए ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी डिटेल्स लीक हो रही है। इस साल के डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी में आईओएस 17, आईपेडओस 17, मेकओएस 14, बॉचओस 10 और टीवीओएस 17 ऑपरेटिंग सिस्टम पेश होने की उम्मीद जताई जा रहा है। आईओएस 17 ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉन्च होने से आईफोन्स में कई नए फीचर्स जुड़ जाएंगे, जो इनकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बना देंगे। खबरों के अनुसार, ऐपल आईओएस 17 अपडेट से ऐपल डिवाइस के कंट्रोल सेंटर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि, बदलाव क्या होंगे इससे जुड़ी जानकारी नहीं है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत

प्रह्लाद सबनानी

भारत को जी-20 समूह की अध्यक्षता मिलना एक वरदान की तरह साबित होता दिखाई दे रहा है। भारत ने हाल ही के वर्षों में कई क्षेत्रों में जो अतुलनीय प्रगति की है, इसे देखकर जी-20 समूह के सदस्य देश आश्चर्यचकित हो रहे हैं। भारत चूंकि जी-20 समूह के सदस्य देशों की विभिन्न बैठकें देश के लगभग समस्त राज्यों के अलग अलग नगरों में आयोजित कर रहा है, इससे देश के समस्त राज्य न केवल इन बैठकों के लिए विशेष तैयारियां कर रहे हैं बल्कि विभिन्न देशों से आने वाले प्रतिनिधि भी इन शहरों में भारत की आर्थिक प्रगति की झलक देख पा रहे हैं।

जी-20 समूह का महत्व इस जानकारी से बहुत स्पष्ट तौर पर झलकता है कि पूरे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में जी-20 समूह के सदस्य देशों की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत की है। विश्व के 193 देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद 95 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इसमें, जी-20 समूह के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था का आकार 75 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। विश्व की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं भारत) को मिलाकर दुनिया की आधी से अधिक अर्थव्यवस्था बनती है। वर्ष 2022 में केवल 18 देशों का सकल घरेलू उत्पाद एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक था। पूरे विश्व का 75 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय विदेश व्यापार जी-20 समूह के सदस्य देशों में होता है। कुल मिलाकर जी-20 समूह के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। अतः स्वाभाविक तौर पर जी-20 समूह का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटना है एवं जी-20 समूह के सदस्य

देशों की जिम्मेदारी वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की है। जी-20 समूह के सदस्य देशों में शामिल हैं- अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, यूरोपीय संघ, टर्की एवं ब्रिटेन।

जी-20 समूह के सदस्य देशों के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से एक विशेष 'डिजिटल इकॉनामी वर्किंग ग्रुप' का वर्ष 2017 में गठन किया गया था। पहले इसे 'डिजिटल इकॉनामी टास्क फोर्स' के नाम से जाना जाता था। भारत में इस वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक 13 फरवरी 2023 को लखनऊ में सम्पन्न हुई थी। इस बैठक में भारत के डिजिटल कायाकल्प के सफर की रूपरेखा प्रदर्शित की गई तथा भारत में डिजिटल पब्लिक आधारभूत ढांचे एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था में साईबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। नैसकोम एवं यूनेस्को द्वारा प्रदान की गई एक जानकारी के अनुसार डिजिटल स्किल गैप की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028 तक 11 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के नुक्सान की आशंका है। अतः इस बैठक में वैश्विक स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया गया। जी-20 समूह के सदस्य देशों के डिजिटल इकॉनामी वर्किंग ग्रूप की दूसरी बैठक हैदराबाद में दिनांक 17 अप्रेल से 19 अप्रेल 2023 के बीच हुई। इस बैठक में भारत को वैश्विक स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार माना गया इससे भारत की जी-20 अध्यक्षता से वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवथा को बल मिलता दिखाई दे रहा है। भारत में हुई डिजिटल क्रांति पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश की गई। जी-20 की अध्यक्षता मिलने के बाद भारत पूरे विश्व में में डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। इस बैठक में हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉड बैंड के उपयोग और प्रभाव पर व्यापक चर्चा हुई है। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय एवं कृषि क्षेत्रों में डिजिटल व्यवस्था को जिस प्रकार सफलतापूर्वक लागू किया है, अन्य देश इस मॉडल को किस प्रकार लागू कर सकते हैं, इस विषय पर भी गम्भीर चर्चा हुई है। साथ ही, 'कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड', 'सस्टेनेबल ग्रीन डिजिटल इंफ्रा' जैसे विषयों को आगे बढ़ाने पर भी सदस्य देशों के बीच सहमति बनी है।

क्रमशः ...

ममता बनर्जी की शर्त पूरा कर पाना कांग्रेस के लिए संभव नहीं

संतोष पाठक

कर्नाटक चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब अखिलेश यादव से लेकर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और शरद पवार सहित कई विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस को आगे बढ़कर बधाई दी। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बधाई देने के साथ-साथ एक कदम आगे बढ़कर यह एलान भी कर दिया कि उनकी पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है लेकिन राजनीति की चतुर खिलाड़ी ममता दीदी ने इस समर्थन के बदले कांग्रेस के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे मानना कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए कतई संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते कद और जनाधार से परेशान ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेलते हुए यह कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां-जहां कांग्रेस मजबूत है वहां-वहां वो कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है लेकिन कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। ममता बनर्जी ने तर्क दिया कि जहां भी (जिन-जिन राज्यों में) कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल मजबूत होता है वहां भाजपा नहीं लड़ सकती है इसलिए वहां पर मजबूत क्षेत्रीय दल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे कर्नाटक में कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं लेकिन उसे (कांग्रेस) बंगाल में मेरे खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। क्या कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी की इस मांग को मानना संभव है ? क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के नाम पर कांग्रेस इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है कि वो मजबूत क्षेत्रीय क्षत्रपों के हाथ में पूरा का पूरा राज्य सौंप दें ? कांग्रेस से निकल कर अपना-अपना क्षेत्रीय दल बनाकर अलग-अलग राज्यों में सरकार चला रहे अपने ही पूर्व नेताओं की वजह से कई राज्यों में पहले से ही अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस क्या अपनी बची-खुची पार्टी को भी इन क्षेत्रीय क्षत्रपों के सामने सरेंडर करने को तैयार है ? सोचने वाली बात तो यह भी है कि ममता बनर्जी की वजह से कांग्रेस को कर्नाटक में कितना फायदा हुआ है ? या ममता बनर्जी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा सकती हैं और अगर इसका जवाब ना है तो फिर कांग्रेस बंगाल को ममता के हवाले कैसे कर सकती है ?

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट तो यह भी है कि अगर वह ममता बनर्जी की मांग मान लेती है तो फिर अन्य राज्यों से भी इसी तरह की मांगें उठनी लगेंगी। अखिलेश यादव कहेंगे कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ न लड़े, नीतीश-तेजस्वी कहेंगे कि कांग्रेस बिहार में उनके खिलाफ नहीं लड़े, नेशनल कांफ्रेंस-पीडीपी इसी तरह की मांग जम्मू-कश्मीर में करेंगे, आम आदमी पार्टी कहेगी कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़े और इसी तरह की मांगें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों से भी आ सकती है तब कांग्रेस क्या करेगी ? ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी ने समर्थन देने की एवज में ऐसी शर्त थोप दी है जिसे कांग्रेस के लिए मान पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि ममता बनर्जी का बयान सामने आते ही कांग्रेस की तरफ से तुरंत अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आ गया। गांधी परिवार के करीबी, पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की शर्त को नकारते हुए कहा कि कर्नाटक चुनाव के पहले ममता बनर्जी ने कभी कहा है कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दो लेकिन अब बंगाल में भी कांग्रेस की पकड़ बढ़ती जा रही है और उन्हें यह लगने लगा है कि कांग्रेस के बिना बंगाल में उनका आगे बढ़ना मुश्किल है। दरअसल, ममता बनर्जी ने जो शर्त खुल कर कांग्रेस के सामने रख दी है, कुछ उसी तरह की इच्छा अन्य तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप भी रखते हैं जो गाहे-बगाहे कांग्रेस को इस बात का अहसास दिलाते रहते हैं कि कांग्रेस उनके राज्य में कितनी कमजोर हो गई है। ये तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप मन ही मन यह चाहते हैं कि विपक्षी दलों की एकता के नाम पर कांग्रेस उनके-उनके राज्यों में उन्हें बड़ा भाई मान ले और जितनी सीटें वो देने को तैयार है उतनी सीटों पर ही लड़े।

यूपी में भगवा लहर का जलवा कायम

मृत्युंजय दीक्षित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भगवा राजनीति का गढ़ बनने की दिशा में अग्रसर प्रतीत हो रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ पहली बार 73 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, 2017 में भी पार्टी को प्रचंड विजय मिली और अब गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में जितने भी चुनाव हो रहे हैं हर चुनाव में भाजपा की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है, 2017 में नगर निगम चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव और अब 2023 के नगर निकाय चुनावों ने तो एक नया अध्याय लिखा है।

निकाय चुनाव 2023 में मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में भाजपा ने सभी 17 नगर निगमों और उसके बाद नगर पंचायत और पालिका चुनावों में भी सीट व वोट प्रतिशत के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी जीत अर्जित कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी समय हुए उपचुनावों में भाजपा ने सपा के मजबूत नेता आजम खां के अंतिम गढ़ को भी ध्वस्त कर दिया। भाजपा की इस विजय से विपक्षी दलों के उत्साह पर पानी फिर गया है और वह 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी में पिछड़ गये हैं वहीं भाजपा अपने सभी सहयोगी दलों के साथ सभी 80सीटों पर विजय का अभियान चलाने जा रही है।

उत्तर प्रदेश में सभी 17 नगर निगमें में भाजपा को मिली विजय बहुत बड़ी है क्योंकि अब किसी भी नगर निगम में निगम संचालन करवाने के लिए निर्दलीय पार्षदों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इस विजय के नायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं जिनकी नियत, नीति और कार्यशैली जनमानस को भा रही है। योगी आदित्यनाथ ने 13 दिनों में 43 जिलों में 50 जनसभाएं और कई रोड शो किये जिनमें नगरीय विकास तथा कानून व्यवस्था की स्थापना पर मुखर रूप से बात की गई। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री का बयान, मिट्टी में मिला देंगे माफिया को और उसके बाद कई खतरनाक माफियाओं पर कार्यवाही ने आमजन का योगी जी पर विश्वास बढ़ाया वहीं मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के तहत सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी सेकुलर दलों के माफियाओं के साथ खड़े हो जाने ने योगी जी की साफ़ नियत का डंका बजा दिया।

राजधानी लखनऊ से लेकर समस्त अवध, बुंदेलखंड, पूर्व व पश्चिम के कई क्षेत्रों में भाजपा पार्षदों के कामकाज से जनता खुश नहीं थी लेकिन फिर भी प्रदेश की जनता ने पहली बार नगर निकाय चुनावों में भी कानून व्यवस्था के नाम पर कई मोहल्लों व गलियों में भाजपा को एकतरफा वोट दिया। भाजपा कार्यकर्ता निगम चुनावों में मतदाता को यह समझाने में कामयाब हो गये कि निर्दलीय व अन्य को पार्षदी के चुनाव में जिताने से कोई लाभ नहीं होने वाला क्योंकि जब एक ही दल का पार्षद विधायक व सांसद रहता है तो काम करने और करवाने में सामंजस्य बना रहता है। यह बात जनता समझती है और इसका परिणाम भी सामने आया उदाहरण के रूप में लखनऊ, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटलजी संसदीय क्षेत्र रहा है, वहां एक बार फिर कमल खिला है और अबकी बार पिछली बार से भी अधिक वोट प्राप्त हुए हैं और पार्षद भी जीतने में कामयाब रहे हैं।

मुख्यमंत्री का मानना है कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत सुशासन, विकास और भयमुक्त वातावरण का नतीजा है जिसे मतदाताओं ने जनादेश दिया है। उप्र में वृहद सांगठनिक ढांचे, समर्पित कार्यकर्ताओं की विशाल सेना और सुनियोजित रणनीति के बल पर भाजपा ने ऐतिहासिक विजय हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में धर्म की ध्वजा पर सवार होकर जातियों का चक्रव्यूह भेदने में सफलता हासिल की है। सभी नगर निगमों में संख्याबल के आधार पर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने का माद्दा रखने वाली जातियों में पैठ बनाने के लिए पार्टी ने प्रभावी मतदाता सम्मेलन आयोजित किये जिसका असर दिखाई पड़ा है। कई सीटों पर बगावती लोगों ने भी अपने तेवर दिखाने के प्रयास किये जिन्हें समझाकर या तो बिठाया गया या फिर समय रहते उन पर कड़ी कार्यवाही की गयी जिसका असर भी परिणामों पर देखा गया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों ने मिलकर एक कुशल रणनीति बनायी और प्रदेशभर का तूफानी दौरा किया। उम्मीदवार चयन से लेकर बूथ प्रबंधन की रणनीति को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारकर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 2023 में भाजपा ने 2017 के मुकाबले बहुत बढ़त बनाई है। वर्ष 2017 में बीजेपी ने 14 नगर निगमों में जीत हासिल की थी और वहीं 198 नगर पालिका परिषद में 70 पालिकाओं में अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। इस बार भाजपा ने 199 में से 87 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। वर्ष 2017 में भाजपा ने 438 नगर पंचायतों में से 100 पर चुनाव जीता था और इस बार भाजपा ने 544 नगर पंचायतों में से 191 पंचायतों में अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। राजधानी लखनऊ के निगम इतिहास में पहली बार भाजपा के 80 पार्षद कमल खिलाने में कामयाब रहे हैं।

भाजपा और अल्पसंख्यक समाज

भाजपा हिंदुत्व व राष्ट्रवाद की राजनीति के बीच अल्पसंख्यकों को भी राष्ट्र धारा में लाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए भाजपा ने केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के सहारे पसमांदा समाज और गरीब मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने में कुछ सफलता प्राप्त की है। प्रदेश की राजनीति में नगर निकाय चुनावों में भाजपा ने पहली बार 395 मुस्लिमों को टिकट दिया था और उसमें 54 मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने बताया कि भाजपा ने विभिन्न पदों के लिये 395 मुस्लिमों को टिकट दिया था जिसमें इनमें से 54 ने विजय प्राप्त की है। दो पार्षद नगर निगम में विजयी हुए, वहीं पांच ने नगर पंचायत अध्यक्ष और 35 ने नगर पंचायत सदस्य के पदों पर विजय प्राप्त की है। पार्षद पदों के लिये लखनऊ के हुसैनाबाद से लुबना अली खान और गोरखपुर से अकीकुल निशां को जीत मिली है। इसके अलावा कई मुस्लिम नगर पंचायत सदस्य भी चुनाव जीते हैं।

इस बार निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण पर विवादों की छाया भी रही और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नये परिसीमन और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ यह चुनाव संपन्न हुए हैं। राजनैतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे थे कि कहीं निगम चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और पसमांदा मुस्लिम समाज आदि का दांव भाजपा के लिये उल्टा न पड़ जाये किंतु उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में भगवा और कमल को निराश नहीं होना पड़ा। इस प्रचंड विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बड़ी चुनौती जनमानस की उम्मीदों पर खरा उतरने की है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

संन्यासोपनिषद् (भाग-10)

गतांक से आगे...

यदि संन्यासी को भिक्षा की विशेष आवश्यकता पड़ जाये, तो उसे म्लेच्छ के यहाँ से भी भिक्षा माँग लेनी चाहिए; परन्तु कभी भी एक ही स्थान से आहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। चाहे वह बृहस्पति के सदृश पूज्य का ही घर क्यों न हो? संन्यासी को सर्वदा याचित अथवा अयाचित भिक्षा के द्वारा निर्वाह करना सर्वथा उचित है।

वायु हर किसी को स्पर्श करता है, अग्नि सभी को जलाता है, जल में सभी तरह के मल-मूत्रादि डाल दिये जाते हैं, फिर भी ये सभी इन दोषों के स्पर्श से प्रदूषित नहीं होते। इसी तरह संन्यासी भी किन्हीं अन्य दोषों से दूषित नहीं होता। अग्नि-धूम्र एवं मूसल के शब्द से रहित, जिस जगह पर अग्नि बुझकर समाप्त हो चुकी हो तथा उपस्थित सभी लोग भोजन कर चुके हों, वहाँ पर ही योगी को मध्याह्न काल के पश्चात् भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति में संन्यासी निन्दनीय परिवार, पतित एवं पाखण्डी-पदच्युत का परित्याग करके समस्त वर्ण जातियों के यहाँ से भिक्षा प्राप्त कर सकता है। संन्यासी के लिए घृत कुत्ते के मूत्र के सदृश है, शहद मदिरा पान के समान है, तेल शूकर के मूत्र के समतुल्य है, लहसुन युक्त पदार्थ एवं उड़द, अपूप (मालपुआ) आदि के पदार्थ गोमांस के सदृश हैं, दूध मूत्र के सदृश है, अतः संन्यासी को सर्वदा घृत आदि से विहीन भिक्षा ही प्रयत्नपूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। घृत एवं सूपादि (चटनी, मिर्च-मसाला आदि) से युक्त पकवान को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। संन्यासी के लिए उसका हाथ भोजन ग्रहण करने का पात्र है।

उस हाथ रूपी पात्र में सर्वदा भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार संन्यासी को दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। दो बार भोजन कदापि न करे। जो मुनि गौ की भाँति केवल मुख से आहार ग्रहण करता है, (संचित नहीं करता) वह सभी में समभाव प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। घृत (आज्य) को रुधिर के समान तथा इकट्ठा किये हुए अन्न को मांस की भाँति त्याग देना चाहिए। गन्ध एवं लेपन को गन्दी वस्तु के समान, नमक को अन्त्यज के समान, वस्त्र को जूँठे पात्र के सदृश, तेल मालिश को स्त्री प्रसंग की भाँति, मित्रों की हँसी-मजाक को मूत्र के समान, घमण्ड को गौ मांस के समान, परिचित मित्रों के घर की भिक्षा को चण्डाल के सदृश, स्त्री को सर्पिणी के समान, सुवर्ण (सोने) को कालकूट के समान, सभा आदि को श्मशानवत्, राजधानी को कुम्भीपाक नरक के समान, एक ही घर के भोजन को मृतक पिण्ड के समान जानकर इनका परित्याग कर देना चाहिए। देवताओं का पूजन-अर्चन कभी न करे। सांसारिक प्रपञ्चों को त्यागकर उसे जीवन्मुक्त बनना चाहिए।

क्रमशः ...

बेटी की शादी में बारातियों को पौधे भेंट किए

चालीस साल पहले जब मैंने पहली बार वृक्षारोपण की शुरुआत की थी, तब मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरा यह काम आगे चलकर इतने वृहद स्तर पर फैल जाएगा। वैसे भी पुलिस की नौकरी के बीच मुझे अपने इस जुनून के लिए समय निकालना शुरू में मुश्किल होता था। मैं केरल के अलपुझा जिले में तैनात 55 वर्षीय पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। वैसे कोई निश्चित गिनती तो नहीं है, पर पंद्रह वर्ष की उम्र में शौकिया शुरू हुआ मेरा वृक्षारोपण का सफर आज आम, बेर, कटहल के करीब एक लाख से ज्यादा पौधों तक पहुँच चुका है। अलपुझा के साथ पड़ोसी एर्नाकुलम जिले में मैंने अधिकांश पेड़ सड़कों के किनारे और वहाँ लगाए है, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं।

हालाँकि मेरा सफर इतना आसान भी नहीं रहा। अधिकांश समय मेरा राज्य केरल सूखे से प्रभावित रहता है, जिस वजह से मुझे पौधों को पानी देने के लिए दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। लोगों की मदद के कारण मेरी मेहनत थोड़ी आसान हो जाती है। कुछ स्थानीय किसान मुझे जैविक खाद के लिए जरूरी मवेशियों का गोबर मुफ्त में देते हैं। मुझे लोगों द्वारा यह दान पुलिस वाला होने के नाते किसी धौंस के कारण नहीं, बल्कि मेरे काम के फायदों से प्रभावित होकर मिलता है। एक पौधे के स्वस्थ विकास के लिए उसे लगाए जाने से लेकर बीस दिनों तक देखभाल करने की आवश्यकता होती है। मैं ड्यूटी के वक्त अपने पास रिवाल्वर तो रखता ही साथ में पौधे लगाने का पूरा इंतजाम भी रखता हूँ। मुझे जहाँ भी लगता है कि वहाँ एक पौधे की जरूरत है, वहाँ पौधा लगा देता हूँ। इसके अलावा मुझे जब भी वक्त मिलता है, मैं पौधे लगाने का काम शुरू कर देता हूँ। मैं अक्सर दूर-दूर तक पौधा लगाने के लिए उचित और सुरक्षित स्थान ढूँढ़ने निकल पड़ता हूँ। इस काम के लिए मैं अपनी हर महीने की तनख्वाह से छह हजार रुपये पर्यावरण की बेहतरी के लिए खर्च करता हूँ। मेरे काम को लेकर शुरू-शुरू में लोग मुझ पर हँसते थे. पर अब वही लोग मेरे नक्शे-कदम पर चल रहे हैं। मैंने इस काम को इस कदर तवज्जो दी कि जब मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, तब बारातियों को 20 हजार पौधे उपहार में दिए थे और उनसे पौधे लगाने की अपील की थी।

छह साल पहले जब विश्व पृथ्वी दिवस पर मुझे एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, तब जिले के पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थानों के लिए निर्देश जारी किया था कि हर थाने में थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी मिलकर पाँच पेड़ लगाएँ। मेरे लिए यह निर्देश मेरे व्यक्तिगत सम्मान से भी बड़ा पुरस्कार था। मुझे खुशी है कि कई दूसरे गैर सरकारी संगठन भी वृक्षारोपण के मेरे काम का अनुसरण कर केरल को हरा-भरा बनाए रखने के लिए आगे आए हैं। इसके अलावा, जब लोक मेरे लगाए पेड़ों की छाया में रुकते हैं और बच्चे उनमें लगे फल तोड़कर खाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे काम का फल मुझे मिल गया। मेरा मानना है कि एक साधारण पौधा भी दूसरों को जिंदगी देता है और लोग पेड़ों में भगवान को महसूस कर सकते हैं यही कारण है कि मुझे पेड़ लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि पेड़ों के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं हैं।

कर्नाटक नतीजे और कुछ चिंताएं

अजीत रानाडे

कर्नाटक में 34 साल के बाद एक रिकॉर्ड टूटा है- सीटों और वोट प्रतिशत, दोनों के मामले में राज्य विधानसभा में कांग्रेस की यह सबसे बड़ी जीत है। इस भारी और निर्णायक जीत के मुख्य कारकों और खिलाड़ियों को लेकर अंतहीन विश्लेषण होते रहेंगे। क्या यह गंभीर एंटी-इनकम्बेंसी का मामला है? साल 1985 के बाद कर्नाटक में किसी सरकार की वापसी नहीं हुई है। क्या यह भ्रष्टाचार, जिसे '40 प्रतिशत कमीशन' का मुहावरा दिया गया, के विरुद्ध रोष के कारण हुआ? धार्मिक मसलों पर बहुत अधिक जोर देने से तो ऐसा नहीं हुआ? क्या लोग नफरती भाषणों से ऊब चुके थे? ये सभी नकारात्मक प्रेरक कारक हैं। फिर इस चुनावी जीत के सकारात्मक प्रेरक कारक क्या रहे? क्या उनमें कांग्रेस घोषणापत्र में उल्लिखित पांच गारंटी- मुफ्त बिजली, न्यूनतम आमदनी की गारंटी, बेरोजगारी बीमा, मुफ्त भोजन और बस पास- को गिन सकते हैं? इनमें से कुछ वादे रेवड़ी, तो कुछ सामाजिक सुरक्षा लग सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, पर रेवड़ियां मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। प्रभावी कारकों के बारे में इस बहस का कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं हो सकता। सभी कारक कुछ न कुछ योगदान देते हैं। मतदाता तार्किक, आर्थिक या वस्तुगत कारकों की अपेक्षा हमेशा भावनात्मक कारकों से अधिक प्रभावित होता है। भारत के सभी राजनीतिक चुनावों पर यह बात लागू होती है। लेकिन इस नतीजे का एक पहलू ऐसा है, जिसको लेकर हमें चिंता होनी चाहिए। यह पहलू है आपराधिक आरोपों वाले तत्वों का उभार। इस संबंध में सुधारों की तत्काल आवश्यकता है, ताकि चुनावी प्रक्रिया साफ-सुथरी हो सके। जीतने वाले ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 55 प्रतिशत हो गयी है, जिन पर आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। साल 2018 में यह आंकड़ा 35 प्रतिशत था। सभी पार्टियों में ऐसे

लोग हैं। गंभीर अपराधों के मामलों के हवाले से देखें, तो 2018 में ऐसे 24 प्रतिशत विधायक थे, जो अब 32 प्रतिशत हैं।

ऐसे अपराधों में हत्या, हमला, अपहरण, बलात्कार या आर्थिक अपराध शामिल हैं। ये गैर-जमानती अपराध हैं, जिनमें पांच साल या अधिक की सजा का प्रावधान है। 'अपराध' की परिभाषा के बारे में कानून बिल्कुल स्पष्ट है। ये केवल पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करने के मामले नहीं हैं। आपराधिक मामले तभी तय होते हैं, जब कोई सक्षम मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करता है और फिर अभियोग निर्धारित करता है। निश्चित ही, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो, तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है। केवल सजायाफ्ता व्यक्ति को ही चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा भी तभी होता है, जब सजा को ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी गयी हो और वहां मामला लंबित न हो। अपील की प्रक्रिया में लंबित मामलों पर फैसला होने में बरसों लग जाते हैं। इसी कारण मौजूदा चुनाव कानून विधानसभाओं और संसद से आपराधिक आरोपों वाले तत्वों को अलग रख पाने में नाकाम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून, 2014 में राज्यसभा में अपने पहले भाषण में इस मुद्दे पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि आपराधिक तत्वों से राजनीति को मुक्त करना उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी। उन्होंने न्यायालयों से लंबित मामलों का जल्दी निपटारा करने का अनुरोध भी किया था। हालांकि उम्मीदवारी रद्द करने के लिए कोई कानून हमारे पास अब तक नहीं है।

आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के मुद्दे पर तीन दशक से अधिक समय से बहस चल रही है। न्यायाधीश जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में 1991 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में इस बारे में सुधार सुझाये थे। न्यायाधीश एपी शाह की अगुआई में विधि आयोग ने 2014 में 244वीं रिपोर्ट में अपराध के आरोपी उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के लिए विस्तृत प्रस्ताव दिया था।

अक्तूबर, 1993 में तत्कालीन गृह सचिव एनएन वोहरा के नेतृत्व में एक समिति ने सरकार को राजनीति के अपराधीकरण पर रिपोर्ट सौंपा था। साफ है कि कम से कम नब्बे के दशक के शुरू से राजनीति पर आपराधिक दाग को लेकर चिंता रही है, पर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या बढ़ती गयी है। यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि लोग ही ऐसे लोगों को निर्वाचित करते रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। पिछले माह अपराधी से नेता बने एक व्यक्ति और उसके भाई की हत्या तब कर दी गयी, जब वे पुलिस हिरासत में थे। टेलीविजन कैमरों ने इस पूरी वारदात को रिकॉर्ड किया। यह गलत हुआ। न्यायिक प्रक्रिया से बाहर की हत्याओं तथा कानून अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति की निंदा की जानी चाहिए।,पर यह भी चिंता का विषय है कि वह व्यक्ति एक बार लोकसभा और पांच बार विधानसभा के लिए चुना गया।

राजनीति को साफ-सुथरा बनाने की समस्या के दो पक्ष हैं। एक पक्ष यह है कि मतदाताओं को अच्छे उम्मीदवारों को चुनना चाहिए और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को पूरी तरह नकार देना चाहिए। दागी नेताओं की मांग घटनी चाहिए, पर यह समस्या भी है कि लोगों के सामने अक्सर अच्छे उम्मीदवार नहीं होते। किसी क्षेत्र में सभी उम्मीदवार ही दागी हों, तो क्या उपाय बचता है? इसका समाधान यही है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। वैसे में अगर यह कहा जाता है कि दर्ज मामले झूठे हैं, तो उन्हें अदालतों से अनुमति लेनी चाहिए। जब सरकार विपक्ष के लोगों पर झूठे मामले दर्ज करती है, तब राजनेता बदले की राजनीति की शिकायत करते हैं। न्यायाधीश शाह समिति 2014 के अपने सुझावों में ऐसी आशंकाओं के बारे में सलाह दी है। अब समय आ गया है कि मतदाता यह कहें कि उम्मीदवारों द्वारा केवल आपराधिक मामलों के बारे में बताना पर्याप्त नहीं है। हमें अब उन्हें अयोग्य ठहराने की ओर बढ़ना चाहिए। आपराधिक मामलों को जाहिर करने का कानून 2003 में आया था। दो दशक बाद स्थिति यह है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अब विधि आयोग की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार कड़ा कानून बनाना चाहिए, जिसमें अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। राजनीतिक वित्त को लेकर पारदर्शिता लाने, दलों में महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के तहत लाने के बारे में भी सुधारों की आवश्यकता है पर सबसे जरूरी यह है कि गंभीर अपराधों के आरोपियों को टिकट न मिले। इतनी बड़ी आबादी में कुछ हजार अच्छे उम्मीदवार मिल ही सकते हैं।

बापू की दिनचर्या

प्रातःकालीन वायु-सेवन

बापू प्रार्थना तथा सूत्र- यज्ञ की भाँति वायु-सेवन को महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य मानते। इसे वे कसरतों की रानी कहा करते। उनका विचार था कि तेज भूख के समय जिस तरह हम सब काम छोड़कर भोजन पर टूट पड़ते और हमें उस समय कुछ अच्छा नहीं लगता, यही स्थिति वायु सेवन का समय होने पर होनी चाहिए। वे टहलने को न केवल भोजन, बल्कि नींद से भी अधिक महत्त्व देते। वायु-सेवन के अपने नियम में वे कभी परिवर्तन नहीं करते। सभी ऋतुओं में उनका टहलना बना रहता। यदा-कदा रेलयात्रा में एक-दो या अधिक दिनों तक रहने के कारण तथा अधिक अस्वस्थ होने पर ही उनका टहलना रुकता, किंतु रेल से उतरने के बाद अपने मुकाम पर पहुँचते ही सबसे पहले वे टहल लिया करते। घूमते समय काम की बात करना बापू अपने लिए अच्छा नहीं समझते। वे उस समय गीता जैसे गंभीर विषय पर मनन करते या मौन रखने के पक्ष में थे, किंतु समय के मूल्य को ध्यान में रखते हुए उनके प्रत्येक मुख्य कार्य के पीछे एक-न- एक आनुषंगिक कार्य लगा ही रहता। यही कारण है कि उस समय भी उनके साथ आश्रमवासियों के अलावा भेंटवार्ता के लिए आए हुए लोगों की अच्छी-खासी भीड़ रहती। साबरमती आश्रम में रोज बापू दोनों समय एक मील टहलते। सेवाग्राम में शुरू में करीब सवा साल तक वे सुबह-शाम टहला करते। अंतिम दिनों में उन्होंने घूमना कुछ कम कर दिया था। सन् 1932 में यरवदा जेल में सरदार पटेल के साथ नित्य नियमपूर्वक आँगन में घूमते समय वे अखबार सुनते। उन दिनों जब कोई अखबार न होता तो माडर्न रिव्यू पढ़ा जाता। दिल्ली में अंतिम दिनों में वे प्रातः भ्रमण के समय अखबार सुनते। सन 42 में आगा खाँ महल में जेल और बगीचे के बीच के बरामदे में घूमते समय वे गीता याद करते। वृद्धावस्था में बाँस की लाठी बापू के पथ का आधार थी। पैरों में तकलीफ हो जाने के बाद से समूह में से उनका कोई-न-कोई कृपाभाजन सहारा देता रहता। अंतिम दिनों में लिखने-पढ़ने के श्रम से हुए आँखों के कष्ट के कारण बापू घूमते समय कुछ दिन आँखों पर पट्टी बाँधते। उनकी गति के साथ अपनी गति को सम रखना कभी-कभी युवकों के लिए कठिन हो जाता। सामान्यतः उनका भ्रमण तेजी से नहीं होता, किंतु पद यात्रा में वे तेज चलते। उनकी ऐतिहासिक दांडी यात्रा का प्रसिद्ध चित्र इस संदर्भ में दर्शनीय है।

क्रमशः ...

भेंट-मुलाकातः मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को चेक और सामग्रियों का किया वितरण

धमतरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बुधवार को धमतरी विधानसभा के ग्राम भटगांव में भेंट-मुलाकात के दौरान हितग्राहियों को प्रतीकात्मक तौर पर सामग्री और चेक का वितरण किया। इनमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) के तहत पांच हितग्राहियों को सामग्री वितरण, जल संसाधन विभाग की ओर से 23 नवनियुक्त उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 30 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमाण पत्र प्रदाय किया। इनमें छत्तीसगढ़ शासन के नवीन सरलीकरण योजना के तहत जारी जाति प्रमाण पत्र, वनग्राम से राजस्व ग्राम अभिलेख अद्यतन और सर्वेक्षण ग्राम का प्रमाण पत्र शामिल है। इसी तरह जनपद पंचायत धमतरी के पांच, नगरपालिक निगम धमतरी के 314 और नगर पंचायत आमदी के पांच हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत स्वीकृति आदेश पत्र का वितरण किया। जनपद पंचायत धमतरी की ओर से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तीन और राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के 5 हितग्राहियों को लाभान्वित किया।

मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की ओर से

49 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 9 लाख 80 हजार रूपये का चेक वितरित किया। इनमें मिनीमाता महतारी जतन योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के हितग्राही शामिल हैं। पशुधन विकास विभाग की ओर से राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत तीन हितग्राहियों को 2 लाख 10 हजार रूपये का चेक, उद्यानिकी विभाग की ओर से राज्य पोषित योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 5 हितग्राहियों को तीन लाख 24 हजार 100 रूपये का चेक वितरित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ऋण योजना के तहत तीन महिला स्व सहायता समूहों को एक-एक लाख रूपये का चेक वितरित किया। इनमें जय बजरंग स्व सहायता समूह सेहराडबरी, जय मां शीतला स्व सहायता समूह बलियारा और न्यू शक्ति सांई स्व सहायता समूह भानपुरी शामिल है। इसी तरह मछलीपालन विभाग की ओर से फुटकर मत्स्य विक्रय योजना, नाव जाल, त्रिवर्षीय समिति अनुदान के तहत 6 हितग्राहियों को कुल 52 हजार रूपये, शिक्षा विभाग की ओर से समग्र शिक्षा के तहत 5 हितग्राहियों को 50 हजार रूपये, कृषि विभाग की ओर से एनएफएसएम योजना और कृषि यंत्रीकरण एवं आत्मा योजना के तहत 5 हितग्राहियों को 16 हजार 600 रूपये तथा समाज कल्याण विभाग की ओर से सहायक उपकरण प्रदाय योजना के तहत 8 हितग्राहियों को 52 हजार 807 रूपये की सामग्रियों का वितरण किया।

रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में धमतरी जिले के पहले वाई-फाई जोन का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बुधवार को धमतरी विधानसभा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ग्राम अछोटा में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में जिले के पहले वाई-फाई जोन की शुरुआत की। इससे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में कार्यरत लोगों को एवं गढ़कलेवा में आने वाले लोगों को निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा स्कूली बच्चे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। वे यहां अध्ययन भी कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस माह की 5 तारीख को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान रीपा को वाई-फाई सुविधा से लैस करने की घोषणा की थी। आज यहां वाई-फाई सुविधा के शुभारंभ से रीपा इस सुविधा से लैस जिले का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन गया है। इस अवसर पर विधायक सिहावा डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन श्री रामगोपाल अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मीना बंजारे मौजूद थे।

ग्राम अछोटा में गढ़कलेवा का लोकार्पण

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्राम अछोटा में निर्मित गढ़कलेवा का बुधवार को लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गढ़कलेवा का अवलोकन किया और स्व-सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत कर गढ़कलेवा में व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री को महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों ने बताया कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन चीला, फरा, ठेठरी, खुरमी, अईरसा, चौसेला, सोहारी अन्य विविध प्रकार के व्यंजन गढ़कलेवा में उपलब्ध रहेंगें। गढ़कलेवा में आने वाले ग्राहकों के बैठने के लिए आउटडोर और इनडोर की व्यवस्था की गई है। जहां पर ग्राहक पसंदीदा व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, उल्लेखनीय है कि गढ़कलेवा में ग्रामीण परिवेश का अनुभव कराने और छत्तीसगढ़ी व्यजनों को बढ़ावा देने के लिए गढ़कलेवा बनाया गया है। गढ़कलेवा में ग्राहकों को वाई-फाई की सुविधा भी मिलेगी।

धमतरी के अछोटा में किया बुनकर गुड़ी का लोकार्पण

धमतरी के अछोटा गांव की रहने वाली लक्ष्मी देवांगन कुछ वर्ष पहले मजदूरी करती थीं, लेकिन शारीरिक कठिनाइयों के चलते उन्हें ये काम छोड़ना पडा. इसके बाद लक्ष्मी को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पता चला. लक्ष्मी ने यहां चार माह का हथकरघा उद्योग का प्रशिक्षण लिया और अपने घर में हथकरघा मशीन लगाया। मां अंगारमोती बुनकर सहकारी समिति मर्यादित अछोटा के माध्यम से लक्ष्मी को काम मिलने लगा और अब लक्ष्मी घर बैठे ही हर माह हजारों रूपए की आय हासिल कर रही है. इस समिति में लक्ष्मी जैसी ही 97 महिलाएं हथकरघा उद्योग से जुड़कर ग्रामीण परिवेश में आर्थिक सशक्तिकरण की नई कहानी लिख रही हैं। अभी तक समिति के सदस्यों के घरों में व्यक्तिगत रूप से बुनकर कार्य किया जाता था। कई समूह सदस्यों के घरों में स्थान की कमी के चलते कार्य अच्छे ढंग से संचालित नहीं हो पाता था । इस समस्या को दूर करने के लिए महात्मागांधी औद्योगिक पार्क योजना अंतर्गत अछोटा गौठान में हथकरघा इकाई की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समिति के सदस्यों को बुनगक गुड़ी लोकार्पित किया है ताकि सदस्यों को कार्य करने में आसानी हो। इसके लिए हथकरघा उद्योग से जुड़े सदस्यों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए उन्हें आम मजदूर से हुनरमंद कारीगर बनाने के लिए आभार भी प्रकट किया।

संक्षिप्त समाचार

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 30 तक विदेश प्रवास पर

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बुधवार को विदेश प्रवास पर रवाना हो गए। यहां से हैदराबाद फिर सिंगापुर होकर आस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में उनका पहला पड़ाव है। आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के दौरे पर वे स्वास्थ्य सेवाओं की आधुनिकत्तम जानकारियों से रूबरू होंगे,इसलिए स्वास्थ्य महकमे के आला अफसरों का दल भी उनके साथ गया हुआ है। 30 तारीख को उनकी वापसी होगी।

महापौर की जाति की जांच सात दिन में कराएं वरना होगा आंदोलन

कोरबा। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद ऋतु चौरसिया ने महापौर राजकिशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए पूर्व में शिकायत की थी। शिकायत के बाद भी जाति प्रमाण पत्र की जांच नहीं की जा रही है। अब पार्षद ने पुनः मामला कलेक्टर के संज्ञान में लाते हुए लंबित शिकायत की जिला स्तरीय प्रमाण पत्र जांच समिति से जांच कराने की मांग की है। पार्षद ऋतु चौरसिया ने बताया कि उनके द्वारा 12 फरवरी 2021 को महापौर राजकिशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र की कूटरचित रूप से बनवाए जाने संबंधित शिकायत कलेक्टोरेट कार्यालय के जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति में की गई थी। अभी तक उक्त जांच की कार्यवाही नहीं की गई है। यह जनहित का विषय है कूटरचित तरीके से दस्तावेज निर्माण कर राजकिशोर प्रसाद महापौर पद पर काबिज हैं। उन्होंने मांग की है कि उक्त जांच कार्यवाही को पूर्ण करा कर न्याय देने हेतु कार्यवाही करें अन्यथा आगामी सात दिवस पश्चात जनता के साथ सुस्त प्रशासनिक रवैये के विरूद्ध आंदोलन के लिए वे बाध्य होंगे।

पत्नी की मृत्यु के बाद बीपीएल परिवार को नहीं मिल रहा राशन

कोरबा। पत्नी की मृत्यु के बाद जिला खाद्य विभाग ने बीपीएल राशन कार्ड को ब्लाक कर दिया है। कार्ड में मेरे अलावा दो दिव्यांग पुत्रियों को नाम भी शामिल है। राशन नहीं मिलने बच्चों के लालन-पालन में कठिनाई आ रही है। इस आशय की शिकायत लेकर ग्राम रिस्दा से पहुंचे ग्रामीण सुख सिंह ने कलेक्टर से की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण ने बताया कि वह रोजी-मजूदरी कर जीवन यापन करता है। उसकी दो पुत्रियां शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। पत्नि के देहांत के बाद खाद्य विभाग ने राशन कार्ड को बंद कर दिया है। सुख सिंह ने बताया विभाग में आवेदन करने के बाद उसके राशन कार्ड को शुरू नहीं किया गया। आवेदक ने राशन कार्ड से सस्ता राशन दिलाने के अलावा आर्थिक सहयोग की मांग कलेक्टर संजीव झा से की है।

छत्तीसगढ़ में कोरोना पर लग रही लगाम, 24 घंटे में 55 नए मरीज मिले

रायपुर। छत्तीसगढ़ मे कोरोना के आंकड़े में अब काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे रफ्तार कम हो रही है। छत्तीसगढ़ मे पिछले 24 घंटे में 55 नए कोरोना मरीज मिले है। वहीं, 2593 लोगों की सैंपल जांच की गई है। इस दौरान औसत पॉजिटिविटी दर 2.12 प्रतिशत रही। आज सबसे ज्यादा 18 नए मामले दुर्ग से सामने आए हैं, इसके अलावा रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेशभर से 99 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज/रिकवर्ड हुए। आज नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में सक्रीय कोरोना संक्रमितों की तादाद घटकर 338 रह गई हैं। मुंगेली से 1, सरगुजा से 1, बेमेतरा से 1, महासमुंद से 1, राजनांदगांव से 2, रायगढ़ से 2, बिलासपुर से 2, बालोद से 3, धमतरी से 4, कांकेर से 4, कोरिया से 5, बलौदाबाजार से 5, रायपुर से 6, और दुर्ग से 18 कोरोना संक्रमित पाए गए, इसके अलावा बाकि जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है।

सुपेला निवासी भान बाई आय प्रमाण पत्र बनाने को लेकर थी परेशान

मितान योजना की मदद से घर बैठे मिला प्रमाण पत्र

भिलाई। मितान योजना के तहत अब तक 8685 लोगों को घर पहुंच सेवा इसके जरिए मिल चुकी है इन हितग्राहियों ने केवल टोल फ्री नंबर 14545 का इस्तेमाल किया था और इन्हें त्वरित रूप से घर पहुंच कर प्रमाण पत्र की सेवा मिल चुकी है। सुपेला निवासी भान बाई आय प्रमाण पत्र बनाने को लेकर काफी चिंतित थी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री मितान योजना की जानकारी हुई। जैसे ही उन्हें यह पता चला कि बस एक नंबर के संपर्क से उन्हें घर बैठे प्रमाण पत्र मिल जाएगा उन्होंने फौरन टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल किया और अपनी समस्या बताते हुए आय प्रमाण पत्र बनाने की बात कही। और अब उन्हें घर पर पहुंचाकर मितान ने आय प्रमाण पत्र दे दिया है। जिससे भान बाई के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं से दफ्तरों के चक्कर काटने और दर-दर भटकने से छुटकारा मिल जाता है साथ ही समय की बचत भी होती है। खुशी की बात यह है कि मितान योजना में अब

राशन कार्ड को भी शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस प्रकार से मितान योजना में 17 प्रकार की सेवाएं हो जाएंगी। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लोगों को दिलाने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निगम की अपील है कि मितान योजना के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार, जन्म प्रमाण पत्र, दुकान एवं स्थापना पंजीयन, जन्म प्रमाण पत्र में सुधार, विवाह प्रमाण पत्र में सुधार, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार नंबर में मोबाइल अपडेशन, निवास प्रमाण पत्र, एससी एसटी प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे अन्य प्रमाण पत्र एवं जरूरी सेवाओं का लाभ लेने के लिए 14545 टोल फ्री नम्बर पर संपर्क करे।

8685 हितग्राहियों को घर पहुंच सेवा का मिला लाभ मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए अब तक 8685 हितग्राहियों को घर पहुंच सेवा का लाभ मिल चुका है। 673 को विवाह प्रमाण पत्र, 213 को मृत्यु प्रमाण पत्र, 250 को जन्म प्रमाण पत्र, 286 को दुकान पंजीयन प्रमाण पत्र, 21 को जन्म प्रमाण पत्र में सुधार, 24 को विवाह प्रमाण पत्र में सुधार, 0 से 5 वर्ष तक के 3149 बच्चों का आधार कार्ड, 94 हितग्राहियों का पैन कार्ड, 1249 लोगों का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट, 828 लोगो का निवास प्रमाण पत्र, 256 जाति प्रमाण पत्र तथा 1642 लोगों का आय प्रमाण पत्र अब तक मुख्यमंत्री मितान योजना के माध्यम से बन चुका है।

एनएच 343 में गढ्डा होने के कारण हो रही दुर्घटनाएं

■ नगर पालिका परिषद में गौरवपथ निर्माण में 10 करोड़ व्यय किए

बलरामपुर। बलरामपुर एक ओर नगर पालिका के द्वारा गौरव पथ निर्माण में करीब 10 करोडो रुपए खर्च कर दिए गए वहीं अब कलेक्टर निवास के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में गौरव पथ के किनारे करीब 2 से 3 फीट गड्ढा हो गया है उसे अब नगर पालिका भरवा भी नहीं पा रही है जिससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है वही आए दिन दुर्घटनाएं गड्ढे कारण होते रहती हैं समय रहते प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि जिला हॉस्पिटल चौक से लेकर साप्ताहिक बाजार तक गौरव पथ का निर्माण नगर पालिका के द्वारा करीब 10 करोड़ रुपय लागत से कराया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में गौरव पथ का निर्माण हुआ था कलेक्टर निवास से महज 100 मीटर की दूरी पर एवं विकास खंड शिक्षा कार्यालय के नजदीक गौरव पथ में सड़क के किनारे 2 3 फीट गड्ढा काफी लंबे अरसे से हैं परंतु नगरपालिका के जिम्मेवार अधिकारियों की नजर इस पर अब तक नहीं पड़ पाई है जबकि इन गड्ढों के चलते कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं वहीं कभी भी बड़ी दुर्घटना घट रखती है

समय रहते प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। दो चार ट्रैक्टर मिट्टी मोरम से गड्ढे को भरा जा सकता है परंतु उसके बाद भी नगरपालिका का इस ओर ध्यान नहीं दिया जाना समझ से परे है।

गौरव पथ भी हो गया हैं कई जगहों पर गड्ढा.. करोड़ों रुपए लागत से बना गौरव पथ भी जगह जगह उखड़ गया है जिसे मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है गौरव पथ में हुए गड्ढे ही दुर्घटना का कारण बन रहे हैं नगर पालिका को तत्काल संज्ञान लेकर उसे चेक भरवाए जाने की आवश्यकता है।

चिटफंड का पैसा वापस मांगने पूर्व मंत्री नावेल ने चलाया अभियान

मालखरौदा। चिटफंड का पैसा वापस मांगने पूर्व मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नोवेल वर्मा का मोर पैसा मोर जमा पूंजी वापस करो वापस करो चला रहे हस्ताक्षर अभियान, आज मालखरौदा में आयोजित पत्रकार वार्ता में वर्तमान सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोप।

आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है । आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री नोवेल वर्मा ने मालखरौदा स्थित विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता किए । वर्मा ने मोर पैसा मोर जमा पूंजी वापस करो वापस करो के तहत चिटफंड कंपनियों में पैसा निवेश किए लोगों को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा वापस करने का वादा किए थे ।

नोवेल वर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जबसे कांग्रेस की सरकार बनी है तब से भ्रष्टाचार चरम पर है चंद्रपुर विधानसभा में भी कांग्रेस के विधायक हैं जिनके संरक्षण में अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हुए हैं । खुलेआम लोगों से पैसा मांगा जा रहा है । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों से किए वादों को पूरा नहीं करने स्थानीय विधायक की निष्क्रियता पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने जानकारी में चंद्रपुर विधानसभा में निवेश किए लोगों का आंकड़ा बताते हुए कहा कि मालखरौदा ब्लॉक के 15561 लोगों ने 43,90,500,56 रुपए , और डभरा ब्लॉक के 12300 लोगों 43,55,50,988 कुल मिलाकर निवेशको ने 87 करोड़ 46 लाख 1 हजार 45 रुपए चिटफंड कंपनियों में पैसा लगाए हैं । जिसे पूर्व मंत्री ने लोगों को उनका पैसा वापस दिलाने हाई कोर्ट , सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही ।

बीजेपी और कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व मंत्री नोवेल वर्मा ने तत्कालीन बीजेपी की सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में चिटफंड कंपनियों को बढ़ावा दिया गया । जिससे हजारों लोगों ने अपना जमा पूंजी कंपनियों द्वारा दिए गए लोकलुभावन वादों के और पैसा दुगुना वापस करने का लालच दिया गया । जिस पर लोगों ने आंख मूंदकर भरोसा कर पैसे लगाए। वहीं वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ने चिटफंड कंपनियों में निवेशकों को पैसा वापस दिलाने वादा किया गया था लेकिन आज तक चंद्रपुर विधानसभा में किसी का जमा पूंजी वापस नहीं किया गया है । उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक भी अपने क्षेत्र के लोगों को पैसा वापस दिलाने कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

रेत माफिया एनजीटी के आदेश को दिखा रहे ठेंगा

कांकेर। महानदी को छत्तीसगढ़ प्रदेश की जीवन रेखा और छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। लेकिन इस गंगा पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। जो इस गंगा को खोखली करने में जुट गए हैं। दिन के उजालों से लेकर रात के अंधेरों में माफिया सक्रिय होकर ह्लज्ञ (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का खुला मखौल उड़ा रहे हैं। सरकारी तंत्र के नाक के नीचे हो रहे कार्य पर सभी आंखे मूंद बैठे हैं।

कांकेर जिले में रेत का अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है। दिन के उजालों से लेकर रात के अंधेरे में भी रेत माफिया अवैध तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। जिले के चारामा क्षेत्र में तीन खदान टाहकापार, बसनवाही, चिनौरी अभी चालू हैं। सरकारी नियमों से शुरू हुए इस खदान से दिन में रेत का परिवहन किया जा रहा है। लेकिन रात के अंधेरे में इस खदान से अवैध रेत का उत्खनन कर चोरी की जा रहा है। रोजाना अंधेरे का फायदा उठाकर नदी से चैन माउंटेन और जेसीबी के सहारे गाड़ियों में लोड कर अवैध रेत बेचा जा रहा है।

सदियों-सदियों तक याद रहेगी मुकेश पिपरिया की कला

■ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश भर से अनेक कलाकार

बालोद। जिले के प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी कलाकार मुकेश पिपरिया के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेशभर के कलाकार पहुंचे। शोक सभा को संबोधित करते हुए कलाकारों ने कहा कि मुकेश पिपरिया की कला सदियों सदियों तक याद की जाएगी। वे एक ऐसे कलाकार थे जो हर विधा में सामंजस्य बिठाकर अपने कला को प्रस्तुत करने में माहिर थे। दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोगों ने भी मुकेश पिपरिया के निधन को अपूरणीय क्षति बताया।

ग्राम कोलियापुरी में उनके निवास स्थान पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कलाकारों ने मुकेश पिपरिया को याद किया। रंग झरोखा के संचालक दुष्यंत हरमुख ने मुकेश के साथ बिताए हुए पल को याद करते हुए बताया कि वे एक ऐसे कलाकार थे जो हमेशा खुश रहते थे और दूसरों को प्रोत्साहित करते थे। निराशा उसके मन में कभी नहीं थी। इसीलिए उनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसको पूरा कर पाना कला जगत के लिए नामुमकिन है। प्रसिद्ध मंच संचालन त्रेता चंद्राकर ने कहा कि मुकेश पिपरिया मे हर विधाओं की कला कूट-कूट कर भरी थी। सभी कलाकारों के बहुत प्रिय थे। मुझे नहीं लगता कि कला जगत में कोई भी उसका प्रतिद्वंदी रहा होगा। दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज केंद्रीय अध्यक्ष डॉ राजेंद्र हरमुख ने कहा कि दिल्लीवार कुर्मी समाज ने मुकेश पिपरिया के रूप में एक हीरा खोया है। इसकी जगह शायद ही कोई ले पाएगा। उन्होंने बताया कि मुकेश बहुत ही हंसमुख व्यक्ति थे। वे हमेशा मुस्कुराते हुए ही मिलते थे। श्रद्धांजलि सभा को जिला पंचायत सदस्य माया बेलचंदान ने बहुत ही मार्मिक संबोधन दिया।

ट्रैफिक पुलिस की तरह हो गई है ईडी, जिसे मन आए नोटिस देकर करते हैं टॉर्चर: बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चल रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, सड़क पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है चालान बुक लेकर। जो भी आए, उसे पकड़े, चालान काटे और अंदर कर दिए। या बोलते हैं कोर्ट में जाकर पटाओ। इसी तरह से ईडी वाले हैं। नोटिस जेब में रखे रहते हैं। जिसे मन आया, उसके नाम से नोटिस, वहीं खड़े-खड़े दे दिया। मुख्यमंत्री बघेल बुधवार को धमतरी रवाना होने से पहले मीडिया से बात कर रहे थे।

भाजपा के मूल एजेंडे की पूर्ति ईडी कर रही

हेलीपैड पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि,

अधिकारी, कर्मचारी और आप भी शासकीय सेवक हैं। यहां जो काम कर रहे, वो भी शासकीय सेवक हैं। उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे, सोने नहीं दे रहे हैं। ये थर्ड डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं वो गलत है। उसके कारण सभी विभागों के काम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा का जो मूल एजेंडा है, उसकी पूर्ति ईडी कर रही है। यहां सरकार अच्छा काम कर रही है। किसान, आदिवासी, महिला, हर वर्ग सरकार से खुश है। हर वर्ग को लगता है, हमारी सरकार है, हमारे लिए काम कर रही है।

सीजीपीएससी चयन में गड़बड़ी है तो सबूत पेश करें, जांच कराएंगे

वहीं सीजीपीएससी चयन में गड़बड़ी को लेकर भाजपा के आरोपों पर भी मुख्यमंत्री बघेल ने जवाब दिया। कहा कि, अगर पीएसी के छात्र राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में उनकी योग्यता पर सवाल उठना दुर्भगायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि, अगर चयन में गड़बड़ी है तो तथ्य समाने लाएं, जांच कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के योग्य छात्रों पर सवाल उठाना सही नहीं है। भाजपा शासनकाल में क्या गड़बड़ी होती थी, हर कोई जानता है। भाजपा अब प्रदेश में सिर्फ माहौल खराब करने का काम कर रही है।

पहले सिर्फ खदानों और नक्सलियों से पहचाना जाता था छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पर सीएम बघेल ने कहा कि, रायगढ़ में एक, दो और तीन जून को इसका भव्य आयोजन होगा। इसके माध्यम से लोक संस्कृति और कला को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि, पहले छत्तीसगढ़ को खदानों और नक्सलियों के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इतनी चीजे है की लोग दांतों तले उंगलिया दबा लेते हैं। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर हुई हाईप्रोफाइल बैठक को लेकर बताया कि, आने वाले समय में कार्यकर्ता सम्मेलन है उस पर विचार विमर्श किया गया है। भरोसा सम्मेलन में सरकार की लगभग महत्वाकांक्षी योजनाओं को राशि का अंतरण किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय नेताओं को शामिल करने की भी कोशिश की जा रही है।

डबल इंजन सरकार मोदी-शाह की, ये केवल धमकी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, डबल इंजन सरकार जैसा कुछ नहीं है। इसका प्रयोग सबसे पहले मोदी सरकार में ही हुआ है। मनमोहन सिंह भी सरकार में रहे, लेकिन उन्होंने कभी डबल इंजन का प्रयोग नहीं किया। यह तो केवल मोदी और शाह की सरकार ही कर सकती है। सीएम ने कहा कि, ये केवल धमकी ही देने का कार्य करते हैं की डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो मोदी जी की कृपा नही होगी। ये जो डबल इंजन की सरकार खुद को कह रहे है यह बिल्कुल गलत है। जनता सब देख रही है।

शराब घोटाले पर भाजपा ने किया पोस्टर लांच

भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बनाने का काम किया: अरुण साव

■ 800 शराब दुकानों पर चस्पा किए जायेंगे पोस्टर, महिला मोर्चा करेगा प्रदर्शन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने एक ओर शराबबंदी का वादा किया और दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने लगातार शराब के नाम पर घोटाले किए। श्री साव ने ऐलान किया कि प्रदेश सरकार के इस शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा महिला मोर्चा जनता के बीच जाएंगे। सभी 800 शराब दुकानों में भाजयुमो शराब घोटाले पर पार्टी द्वारा जारी पोस्टर चस्पा करेगा और महिला मोर्चा इस मुद्दे को लेकर जिलों में प्रदर्शन करेगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शराब घोटाले को लेकर आयोजित पोस्टर विमोचन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्ण शराबबंदी का वादा करके कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, लेकिन फिर 4 साल तक इस पर अमल करने के बजाय वह खामोश बैठी रही। फिर कमेटी बनाकर अध्ययन के नाम पर खानापूर्ति का प्रयास हुआ, और अब मुख्यमंत्री बघेल शराबबंदी के अपने वादे से मुकर गए हैं। श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग इस बात को जान रहे थे कि प्रदेश की 800 शराब दुकानों में दो अलग-अलग कैश काउंटर होते थे, जिसमें से एक कैश काउंटर का पैसा कांग्रेस पार्टी के खजाने में जा रहा था। श्री साव ने कहा कि जिस प्रकार डिस्टलरीज से सीधे शराब दुकानों में नकली होलोग्राम के जरिए नकली शराब भेजी और बेची गई, वह छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों की खुली लूट है। श्री साव ने कहा कि शराब घोटाला करके कांग्रेस का खजाना भरने के लिए भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बनाने का काम किया। श्री साव ने कहा कि प्रदेश सरकार की यह नकली शराब छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ कर रही है। अभी एक दिन पहले ही जांजगीर-चाँपा जिले में नवागढ़ के ग्राम रोगदा में चार लोगों की मौत नकली शराब पीने से हुई है। ऐसे न जाने कितने लोगों के स्वास्थ्य व जीवन से खिलवाड़ करने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है।

श्री साव ने कहा कि 2,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला छत्तीसगढ़ की जनता को शर्मसार करने वाला है। श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को देशभर में बदनाम करने वाला यह शराब घोटाला ईडी ने जब से उजागर किया है, उससे छत्तीसगढ़ में इस तरह का माहौल बना है कि आम लोग छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के घोटालों से त्रस्त हो गए हैं।

इस मौके पर भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन सहित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय, विक्रम उसेंडी, पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, महामंत्री द्वय केदार कश्यप व ओ.पी. चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता द्वय अनुराग सिंहदेव व केदार गुप्ता, रायपुर संभाग प्रभारी सौरभ सिंह, बिलासपुर संभाग प्रभारी किरण देव सिंह, सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव उपस्थित थे।

जनरेशन कंपनी में 86% राखड़ का हुआ उपयोग

रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में उत्सर्जित राखड़ का उचित निपटान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सभी संयंत्रों से 86 प्रतिशत राखंड का प्रबंधन और उसके बेहतर उपयोग करने में सफलता हासिल की गई है। यह अब तक का सर्वाधिक राखड़ उपयोग का प्रतिशत है।जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एसके कटियार ने बताया कि बेहतर प्रबंधन के परिणामस्वरूप यह संभव हो सका। कंपनी राखड़ प्रबंधन के लिए सजग है और इसके लिए विभिन्न स्तर पर लगातार प्रयास किये जा रहे है। उत्पादन कंपनी के तीनों संयंत्रों से निकलने वाले राखड़ का उपयोग विभिन्न निर्माण एवं अन्य गतिविधियों में किया जा रहा है। स्टेट पॉवर कंपनी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में विदयुत गृहों की राखड़ उपयोगिता का औसत जहाँ 86 प्रतिशत रहा जो अब तक एक वर्ष में राखड़ के अधिकतम उपयोग का रिकार्ड है। वहीं तीनों संयंत्रों में सबसे अधिक अटल बिहारी ताप विद्युत गृह मड़वा का 117 प्रतिशत रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विदयुत गृह कोरबा ने 86 प्रतिशत निपटान किया तथा हसदेव ताप विद्युत गृह ने 70 प्रतिशत का उपयोग कर पर्यावरण मंत्रालय के प्रावधानों के अनुरूप राखड़ प्रबंधन करने में सफलता हासिल की। इस प्रकार अधिसूचना में निहित दण्ड प्रावधान के तहत राज्य की जनरेशन कंपनी के ऊपर वर्ष 2022-23 में बेहतर राखड़ प्रबंधन को देखते हुए किसी प्रकार का अर्थदण्ड प्रत्यारोपित नहीं किया जाएगा।प्रावधान के तहत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में राखड़ बांधों के स्थिरीकरण की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना है। इसके लिए कोरबा पूर्व स्थित पोड़ीमार फेस 1 एवं 2 तथा पी. ए. बी. पोंड क्र 2 राखड़ बांध, कोरबा पश्चिम स्थित डगनियाखार राखड़ बांध तथा लोतलोता राखड़ बांधों का स्थिरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

ढाई साल के फार्मूले पर बोले टीएस सिंहदेव, "मैंने कभी हा नहीं कहा"

रायपुर। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही कवायद ज़ारी है। इस बीच एक बार फिर छत्तीसगढ़ के ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री की चर्चा हवा में तैरने लगी है। राज्य के कद्दावर मंत्री टी एस सिंहदेव ने साफ कर दिया है कि उन्होंने इस फार्मूले को लेकर कभी भी कोई राय जाहिर नहीं की है। न कभी हां कहा और न कभी न कहा।

सूबे में ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री को लेकर लंबे अरसे से चल रही चर्चाओं के मसले पर सिंहदेव का कहना है, ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री की चर्चा चली मीडिया में, स्पैक्युलेशन हुआ जैसा अभी कर्नाटक में हो रहा है, मगर किसी ने तो यह बात नहीं कही।

शेयरिंग की बात आई, जिस दिन से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, उसी दिन से मीडिया में यह बात चर्चा में आई। अब यह तो मीडिया ही बताए कि उनके क्या स्रोत हैं। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि ढाई साल की बात थी और कभी भी यह नहीं कहा कि ढाई साल की बात नहीं थी।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सिंहदेव ने कहा कि मैंने हमेशा यही बात कही है कि यह सब पार्टी हाईकमान ही तय करता है, यह निर्णय हाईकमान स्तर के हैं और वही तय करते हैं। हां यह भी सही है कि कहीं भी यह नहीं होता कि मुख्यमंत्री का टर्न लिखा होता है। मुख्यमंत्री को हमने बदलते भी देखा है। कई मुख्यमंत्री डेढ़ दशक तक रहे और कोई एक दशक।

शीला दीक्षित और दिग्विजय सिंह के उदाहरण हैं। वहीं कांग्रेस में एक टर्न में तीन मुख्यमंत्री देखें, भाजपा में भी देखे हैं। सभी पार्टियों में कोई फिक्स नहीं रहता, स्पैक्यूलेशन रहता है कि फर्स्ट रनर यह थे, इनमें से शेयरिंग हो सकती है। वह चल पड़ता है, ढाई ढाई साल का चल पड़ा और खूब चला।

इसी साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए क्या संभावनाएं नजर आती हैं, इस सवाल पर सिंहदेव का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उन्हें लगभग पूरा कर दिया है, कुछ रह गए हैं, तो वे जल्दी ही पूरे होंगे। किसान कर्ज माफी की बात हो या धान के समर्थन मूल्य वृद्धि की और मोटे अनाज के लिए समर्थन मूल्य तय करने की, अंग्रेजी माध्यम के सरकार स्कूल खोलने की, जितने भी वादे किए गए थे, उनमें से अधिकांश पूरे कर दिए गए हैं। इन्हीं सब को लेकर पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी।

2 हजार करोड़ का शराब घोटाला मनगढ़ंत: शुक्ला

रायपुर। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विगत 1 माह से ईडी द्वारा राज्य में 2019 से 2022 के तीन वर्षों में कथित शराब घोटाले में 2000 करोड़ रू. का भ्रष्टाचार होने एवं सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस पूरे मनगढ़ंत आरोपों की पटकथा 3 साल पहले शुरू हो गयी थी। आसन्न विधानसभा चुनावों को देखते हुये केंद्र सरकार ने ईडी के माध्यम से यह षड़यंत्र रचा है।

आईटी की छापेमारी फेल हो गयी अपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये। आईटी की उसी कार्यवाही को आधार बना कर ईडी कहानी गढ़ रही है। जब ईडी भी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाई तो गन पॉइंट पर डरा धमका कर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। सरकार में बैठे लोगों का नाम लेने दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। ईडी द्वारा राज्य में गवाहों के साथ किये जा रहे अत्याचार के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल द्वारा राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए यह बताया कि अनवर ढेबर, पप्पू ढिल्लन तथा सारे अधिकारियों (गवाहों) को मुख्यमंत्री जी का झूठा नाम लेने के लिये भी प्रताड़ित किया जा रहा है। श्री कपिल सिब्बल द्वारा यह भी बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को प्रताड़ित करने का मुख्य उद्देश्य चुनावी वर्ष में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को ठप्प करना मात्र है। देश के अन्य किसी भी भाग में ऐसी घटना कभी देखी सुनी नहीं गयी है। श्री सिब्बल के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए बेंच द्वारा ईडी के अधिवक्ता को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

ईडी की तथाकथित घोटाले की सच्चाई इस प्रकार है-27-28 फरवरी 2020 को दिल्ली की आयकर टीम ने राज्य के शराब कारोबार से संबंधित 28 लोगों के यहां छापेमारी की कार्यवाही की गयी थी। इतनी बड़ी कार्यवाही में बरामद चल-अचल संपत्ति की आयकर विभाग द्वारा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गयी कि वे छापे पूरी तरह से फेल हो गये थे। उसके पश्चात सभी स्थानों में जब्त मोबाइल फोन से रिकव्हरर्ड व्हाट्सअप चैट्स के आधार पर सभी संबंधितों के ब्यान आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली में दर्ज किये गये। शराब से संबंधित सभी कारोबारियों एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा राज्य में शराब के व्यवसाय में भ्रष्टाचार होने अथवा बड़ा घोटाला होने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया गया था। आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा लिये गये समस्त ब्यानों की प्रतियां संलग्न हैं। यह उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा लिये गये बयान भी शपथ पत्र पर लिये जाते हैं तथा ब्यान झूठे पाये जाने की दशा में दोषी भारतीय दंड संहिता की धारा 191 एवं 193 के तहत दंड का भागीदारी होता है। वर्ष 2020 में ही दिल्ली के आयकर अधिकारियों द्वारा छत्तीसगढ़ में मारे गये छापों के दौरान जब्त मोबाइल ट्रांसक्रिप्ट्स (जो अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 की अवधि के थे) ई.डी. को भी उपलब्ध करा दिये गये थे। ई.डी. के अधिकारी विगत दो-ढाई वर्षों से आयकर विभाग से प्राप्त रिपोर्ट को दबा कर बैठे रहे। राज्य में विधानसभा चुनाव निकट आने पर आयकर विभाग से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर ईडी द्वारा अचानक 29 मार्च 2023 को पुन: लगभग उन्हीं स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी, जिन स्थानों पर 3 वर्ष पूर्व आयकर विभाग द्वारा छापे मारने की कार्यवाही की गयी थी। ई.डी. के छापे भी पूरी तरह असफ्ल हो गये क्योंकि इन छापों में चल-अचल संपत्ति की ऐसी बरामदगी नहीं हुई।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

पीएससी चयन पर सवाल उठाना कुंठित भाजपाइयों की निराशा का प्रमाण-वर्मा

रायपुर। पीएससी चयन सूची पर भाजपा नेताओं की अनर्गल बयानबाजी पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोकसेवा आयोग एक संवैधानिक एजेंसी है, यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। कांग्रेस सरकार में हमेशा से ही संवैधानिक संस्थानों की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप उनकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखने की जिम्मेदारी, सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भर्ती, परीक्षा और चयन प्रक्रिया में राज्य सरकार का सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। संवैधानिक संस्थानों, केंद्रीय जांच एजेंसियों और राजभवन तक का राजनीतिक उपयोग भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन राज में 15 साल के कुशासन को भी भोगा है। रमन सरकार के दौरान 2003 और 2005 में पीएसी भर्ती घोटाला भी सर्वविदित है। 2003 के मामले में अभ्यर्थियों के शिकायत पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि रमन सरकार के दौरान उक्त भर्ती में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी साफ दिख रही है। जांच और स्कैलिंग में षडयंत्र पूर्वक किए गए गड़बड़ी को लेकर उच्च न्यायालय ने कड़े कमेंट किए।।

कांग्रेस की करतूतों का भंडाफोड़ करेगी भाजपा- बृजमोहन

रायपुर। पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार धोखेबाज सरकार है। किसानों को 25 सौ रुपए धान की कीमत देने के आड़ में किसानों के खेतों को नापा जा रहा है,मेड़ों को तोड़ा जा रहा है। भूपेश बघेल को यह सरकार गरीब किसानों को अन्य सुविधाओं से वंचित रख रही है, उन्हें ठगने का काम कर रही है।बृजमोहन ने कहा कि आज समूचे छत्तीसगढ़ में समस्याओं का अंबार है। गांव-गांव में सड़कों की हालत बेहद दयनीय है,गड्ढे तक नही भरे जा रहे। जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है। भरी गर्मी में बिजली की कटौती ग्रामीण जन परेशान हैं। स्कूलों की व्यवस्था चरमरा गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। पानी के लिए त्राहि त्राहि मची हुई है। क्या यह सब सुविधाएं किसानों को बेहतर नहीं मिलनी चाहिए? उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सिर्फ छलावा करके छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं। उनकी कांग्रेस सरकार जहां जन समस्याओं की अनदेखी कर रही है वही घर-घर शराब पहुंचा सर नशे के कारोबार को बढ़ाने में लगी हुई है।बृजमोहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की इस लुटेरी कांग्रेस सरकार के पाप का घड़ा भर गया है। भारतीय जनता पार्टी अब इस कांग्रेस सरकार का भंडाफोड़ करेगी। और उनकी करतूतों को जनता के सामने लाएगी।

मोदी सरकार 9 साल में वादा निभाने में नाकाम : मरकाम

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे में विफल और नकारा साबित हुई है। नोटबंदी, जीएसटी मोदी सरकार के वह निर्णय है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। 100 दिन में महंगाई कम करने का वायदा करने वाली मोदी सरकार के राज में महंगाई बढ़ गयी। खाद्य तेल, राशन सामग्री, पेट्रोल-डीजल के दाम दुगुने हो गये जनता बेहाल है। कांग्रेस सरकार के अप्रैल 2014 के मुकाबले आज 8 साल बाद डीजल पर एक्साईज ड्यूटी 344 प्रतिशत बढ़ी है, और पेट्रोल पर एक्साईज ड्यूटी 110 प्रतिशत बढी है। घरेलू गैस सिलेंडर जो कांग्रेस सरकार में अप्रैल-मई 2014 में 410 रू. का था, वह आज 1100 रू. को पार कर गया है। साल 2013-14 में कांग्रेस सरकार गैस पर सालाना 46458 करोड़ रू. की सब्सिडी देती थी, ताकि जनता को सस्ती गैस मिले। मोदी सरकार ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। मोदी जी ने युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 9सालों में कम से कम 12.5 करोड़ नौकरियां छीन ली। भारत को साल 2028 तक 34.35 करोड़ नए रोजगार सृजन करने होंगे। यानि हर साल 3 से 4 करोड़ नई नौकरियां।

रामायण महोत्सव का विरोध भाजपा का कालनेमि चरित्र -सिंह

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ के भांचा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जीवनी उनके कार्य पर आधारित अंर्तराष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन करवा रही है जिसमे देश विदेश से रामकथा वाचक रामायण मंडली रामलीला मण्डलियों का दल शामिल होने आ रहे है तो भाजपा के पेट मे दर्द क्यो हो रहा है? भाजपा ने अंर्तराष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन का विरोध कर अपने कालनेमि चरित्र को जनता के आगे प्रदर्शित किया है। भाजपा सिर्फ वोट लेने और चंदा लेने के तक ही जय श्री राम का नारा लगाती है कभी रामकाज नहीं करती है। राम वन गमन पथ एवं विश्व की एकलौती मंदिर माता कौशल्या की मंदिर को विकसित मत करिये? श्री राम जी के नाम से वोट लेने के बाद भाजपा के नेता सत्ता सुख भोगने में जुट गए कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने में रमे रहे है। रमन सरकार के दौरान भाजपा के नेता पंडाल लगाकर दीनदयाल की कथा सुनते थे वह कभी रामायण कथा नहीं सुने। कभी राम वन गमन और माता कौशल्या का मंदिर, रामायण कथा कराने की सुध नहीं ली। आज जब छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा और हमारे पौराणिक महत्व के अनुसार जब अंर्तराष्ट्रीय रामायण पाठ हो रहा हैं तब भाजपा विरोध करके अपने काले कारनामे में पर्दा करना चाहती है।

भाजयुमो करेगा लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने लोक सेवा आयोग की हाल ही घोषित चयन सूची को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कल 18 मई को भाजयुमो लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करेगा।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने इस दौरान प्रदेश में हाल ही घोषित लोक सेवा आयोग की चयन सूची को लेकर भी प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। श्री साव ने कहा कि पीएससी की घोषित चयन सूची को लेकर प्रदेश के युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पीएससी की चयन सूची को देखकर यह साफ हो गया है कि यह छत्तीसगढ़ की युवा प्रतिभाओं के साथ सीधी-सीधी धोखाधड़ी है, छल है, अन्याय है। श्री साव ने कहा कि रात-दिन पुरुषार्थ करने वाले प्रदेश के युवा अपने उज्ज्वल भविष्य की रचना कर जीवन को संवारने के लिए परिश्रम करते हैं, उन्हें प्रदेश सरकार ने ठेंगा दिखाने का काम किया है। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति के साथ जो छल किया है, वह बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। श्री साव ने कहा कि इसे लेकर भाजयुमो 18 मई को लोक सेवा आयोग का घेराव करेगा और युवाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। श्री साव ने कहा कि चयन सूची को देखकर युवाओं में जिस प्रकार से आक्रोश पनपा है। जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर परीक्षार्थी युवाओं ने शंका व्यक्त की है।

मूणत ने रामकुंड में पीएम आवास योजना का स्वीकृति पत्र दिया

■ पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत के हाथों भवन निर्माण अनुज्ञा पाकर खिले चेहर

रायपुर । रायपुर पश्चिम विधानसभा के रामकुंड इलाके में मकान बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए इसकी राह आसान हो गई है। बुधवार को शहीद चूड़ामड़ी नायक वार्ड क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान के तहत स्वीकृत पात्र लोगों भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को अनुज्ञा प्रमाण पत्र का वितरण का कार्यक्रम पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेश मूणत की अध्यक्षता में और पार्षद दीपक जायसवाल की उपस्थिति में किया गया।इस दौरान राजेश मूणत द्वारा हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री राजेश मूणत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में एक अहम पड़ाव तय किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में जन-जन की भागीदारी से ही काफी संख्या में घरों का निर्माण संभव हो पाया है,लेकिन कांग्रेस सरकार के असहयोग की वजह से छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों आज भी लोग पक्के मकान से वंचित हैं। उन्होंने मकान का सपना पूरा करने वाले हितग्राहियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सभी जरूरतमंद नागरिकों के साथ खड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एक -एक कार्यकर्ता आपके हितों की पूर्ति के लिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। मूणत ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर मूलभूत सुविधाओं से युक्त घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं,इसलिए मैं आज के इस अवसर पर गृहस्वामिनी बहनों को विशेष बधाई देता हूं।

कलेक्टर डॉ भुरे ने प्रावीण्य सूची में आने वाले बच्चों को किया सम्मानित

रायपुर।कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने आज यहां कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कलेक्टर सभाकक्ष में 10वीं-12वीं कक्षाओं में प्रावीण्य सूची में शीर्ष में आने वाले रायपुर जिले के बच्चों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने सभी बच्चों से बात की तथा पालकों और शिक्षकों को बधाई भी दिया।

इस अवसर पर कलेक्टर डॉ भुरे ने 10वीं कक्षा में जिले की प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले चित्राक्षी साहू, अनिग्धा महापत्रा, ऋषभ देवांगन, चांदनी पटेल और संस्थिता कोस्टा तथा 12वीं कक्षा में जिले की प्रावीण्य सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले न्यासा देवांगन, रेशम खत्री, झरना साहू, नेहा निषाद, दिव्या सुंवर, कुंदन बियानी, मुस्कान सिंह, आदित्य सोनी कृष्णा सेखेरिया और नंदिनी साहू को सम्मानित किया। उन्होंने सभी को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ भी दीं।मेरिट में अपनी जगह बनाने वाले विद्यार्थियों को लगन और कड़ी मेहनत के साथ आगे की पढ़ाई करने प्रेरित किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.